वर्ष-15, अंक-119
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

आज का विचार

सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है!

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

सिटी चीफ

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

इंदौर, शनिवार 03 अगस्त 2024

सीबीआई करेगी कोचिंग सेंटर हादसे की जांच, दिल्ली हाईकोर्ट ने अफसरों और पुलिस को लगाई फटकार...

शुक्र है पानी का चालान नहीं काटा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। अदालत ने पीठ ने एमसीडी व पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है और यह एक सामान्य बात हो गई है। वहीं एसयूवी के चालक को गिरफ्तार करने का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच के संबंध में जनता को कोई संदेह न हो। यह घटनाक्रम एक जनहित याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के पानी से भरे बेसमेंट में डूबने से तीन अभ्यर्थियों की मौत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई है।

पीठ ने केंद्रीय सतर्कता आयोग आयुक्त को सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि जांच समय पर हो। पीठ ने कहा घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच के संबंध में जनता को कोई संदेह न हो, यह अदालत जांच को सीबीआई को सौंपती है।

आदेशों के साथ पानी की तरह व्यवहार: पीठ ने कहा चूंकि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग करता है, इसलिए यह अदालत आयुक्त को जांच की निगरानी के लिए एक सदस्य नियुक्त करने का निर्देश देती है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि दिल्ली में नालियों जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थिति न केवल पर्याप्त है, बल्कि उनका रखरखाव भी ठीक से नहीं किया गया है और हाल की त्रासदियों ने दिखाया है कि नागरिक एजेंसियों को दिए गए उसके आदेशों का सही अर्थों में पालन नहीं किया जा रहा है और उनके साथ पानी की तरह व्यवहार किया जा रहा है।

सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया?- पीठ ने एसयूवी मालिक की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया गया? पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार और निर्दोष को छोड़ देते हैं। आप निर्दोष को गिरफ्तार करेंगे और दोषी को छोड़ देंगे हैं, तो यह बहुत दुखद होगा।

पानी आया तो लाइब्रेरियन भाग गया: सुनवाई के दौरान पेश स्थानीय पुलिस उपायुक्त ने कहा कि जब पानी आया तो वहां पर करीब 20 से 30 बच्चे थे। अचानक काफी तेजी से पानी आया। यह एक बड़ा सा हॉल था। जब यह हुआ तो वहां का लाइब्रेरियन भाग गया था। काफी बच्चे निकालने में कामयाब हुए लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि शीशा टूट गया। एक टेबल के कारण भी निकलने में दिक्कत आई। वहां पर कोई बायोमेट्रिक नहीं था। डीसीपी ने कहा कि हमारा बीट कांस्टेबल भी वहां पर पहुंचा था उसके गले तक पानी आ गया था बाद में हमने एनडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव का काम किया।

एसयूवी चालक से माफी मांगना चाहिए: अदालत ने एसयूवी मालिक की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हमको इन पर विश्वास नहीं है। अदालत ने कहा यह विश्वास का सवाल नहीं है एक्सपर्ट को लाने की बात है। बता दें कि श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन, तीनों सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रो की 27 जुलाई की शाम को ओल्ड राजिंदर नगर में राव के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बारिश का पानी घुसने से मौत हो गई थी।

मप्र में 9 बांध खुले, निकला सैलाब

भोपाल। मध्यप्रदेश के अधिकतर जिलों में गुरुवार से शुरू हुआ भारी बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। इसके चलते प्रदेश के 9 बांधों के गेट भी खोल दिए गए। भोपाल में कोलार डैम के 4, कलियासोत के 10, भदभदा के 6, नर्मदापुरम में तवा डैम के 9, अशोकनगर में राजघाट के 8, जबलपुर में बरगी के 7, रायसेन के बारना डैम के 6, विदिशा में हलाली डैम के 2 और छिंदवाड़ा में माचागोरा डैम के 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इस सीजन में पहली बार शुक्रवार सुबह आठ बजे तवा बांध के पांच गेट खोले गए। दोपहर 12 बजे तक चार और गेट खोल दिए गए। अब बांध के 9 गेट पांच फीट तक खुले हैं। बांध से 72 हजार 747 क्यूसेक पानी तवा नदी में छोड़ा जा रहा है, जो नर्मदा नदी में पहुंचेगा। लगातार पानी छोड़ने से नर्मदा नदी उफान मारेगी, इससे निचले इलाके जलमग्न होने का खतरा बढ़ गया है। मध्यप्रदेश में बारिश के स्ट्रांग सिस्टम के चलते इंदौर और राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है, जिससे प्रदेश के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जगह-जगह जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

कहां कितनी बारिश: प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन भर बारिश का दौर चला। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सीधी में सबसे ज्यादा 3.7 इंच बारिश हुई। राजधानी भोपाल और नरसिंहपुर में सवा इंच पानी गिर गया। रायसेन और सतना में 3 इंच, पचमढ़ी, टीकमगढ़ में 1 इंच, रतलाम, उज्जैन और मलाजखंड में पौन इंच बारिश दर्ज की गई। बैतूल, नर्मदापुरम, धार, रीवा, उमरिया, गुना, इंदौर, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला में भी बारिश का दौर चलता रहा।

वायनाड भूस्खलनः पांचवें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी

300 से ज्यादा की मौत अब भी 200 लोग लापता

वायनाड में भूस्खलन के पांचवें दिन शनिवार(3 अगस्त) को भी रेस्क्यू टीमें मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश में जुटी हैं। हाइटेक डिवाइसेज और खोजी कुत्तों की मदद से जिंदा बचे लोगों की तलाश जारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फेसबुक पर पोस्ट कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। सीएम विजयन ने कहा कि राडार मामूली हरकतों का पता लगाया जा रहा है। इससे एक उम्मीद जगी है कि जो भी लोग मलबे में दबे हैं उन्हें जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। इस आपदा के चार दिन बाद, प्रशासन ने यह बात मान ली है कि राहत और बचाव कार्यों के लिए मजबूती से कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की ओर से भूस्खलन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत होने की बात कही गई है। अब भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। सेना मोबाइल के लास्ट लोकेशन के हिसाब से भूस्खलन के बाद लापता हुए लोगों की तलाश में जुटी है। शुक्रवार को, सेना ने पदावेट्टी कुन्नू में एक ही परिवार के चार लोगों को जीवित बचाया।

मुख्यमंत्री विजयन ने बचाव कार्य की सराहना की: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि बचाव कार्य पूरा हो चुका है। घायल लोगों का इलाज चल रहा है। अब मलबा हटाने और मृतकों को निकालने का काम चल रहा है। सेना ने बचाव कार्य में सराहनीय काम किया है। तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने वायनाड के पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की है।

एक ही रात में चार बार हुआ भूस्खलन

29-30 जुलाई की रात वायनाड में चार बार भूस्खलन हुआ। चार गांव बह गए। सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीटी मैथ्यू ने कहा कि मुंडक्कई, चूरलमला, अट्टामला और नूलपुझा गांवों में बचाव कार्य पूरा हो चुका है। अब केवल मृतकों की तलाश की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी देर रात (भारतीय समय) इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा - हम इस कठिन समय में भारत के साथ हैं।

राहुल गांधी ने किया भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुरुवार को वायनाड पहुंचे। राहुल ने कहा कि उन्हें अपने पिता की मृत्यु के समय जैसा ही महसूस हो रहा है। कांग्रेस पार्टी वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी। राहुल ने वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीता था। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी और अब प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। वायनाड कलेक्टर मेघश्री ने कहा कि भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित मुंडक्कई और चूरलमला क्षेत्रों को छह जोन में बांटा गया है। यहां बचाव दल डॉग स्क्वाड के साथ लापता लोगों और मृतकों की तलाश कर रहे हैं। इसमें सशस्त्र बलों और पुलिस की 40 टीमें शामिल हैं।

सरकार का आदेश- सिगरेट शराब के विज्ञापन न करें खिलाड़ी

नई दिल्ली। अब देश का कोई भी खिलाड़ी शराब या धूम्रपान का विज्ञापन करता दिखाई नहीं देगा। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल ने बीसीसीआई और साई को पत्र लिख खिलाड़ियों से तत्काल शपथ पत्र लेने के लिए कहा है। पत्र में डॉ. गोयल ने लिखा है कि खिलाड़ी खासतौर पर क्रिकेटर देश की युवा आबादी के लिए रोल मॉडल हैं। ये युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि यह दुर्भाग्य है कि अकसर खेल जगत के दिग्गज सितारे सिगरेट, बीड़ी या फिर पान मसाला का विज्ञापन करते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी से स्वास्थ्य महानिदेशक ने देश की आबादी को स्वस्थ रखने के संकल्प में सरकार का सहयोग देने के लिए कहा है। उन्होंने अपील की है कि आईपीएल या अन्य क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान इस तरह के विज्ञापनों का प्रसार नहीं होना चाहिए। साथ ही खिलाड़ियों को इन विज्ञापनों से दूर करने के लिए तत्काल उपायों पर गौर करना चाहिए। डॉ. गोयल ने सुझाव दिया है कि बीसीसीआई खिलाड़ी से एक शपथ पत्र ले सकती है, जिसमें वह इन विज्ञापनों से खुद अलग रखने का वादा करेंगे। इसी तरह का एक पत्र भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के महानिदेशक संदीप प्रधान को लिखा गया है। दरअसल, देश के चर्चित खिलाड़ी और फिल्म स्टार अक्सर विभिन्न माध्यमों में तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करते दिखाई देते हैं। इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव से लेकर वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर और फिल्म अभिनेता अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान तक शामिल हैं।

वायनाड त्रासदी के तीन दिन बाद चमत्कार परिवार के 4 लोग जिंदा निकले

वायनाड। केरल के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन के जख्म तीन दिन बाद भी हरे हैं। त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है, वहीं 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। एक दिन पहले केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा था कि मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है लेकिन, अब किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं बची है। इस बीच शुक्रवार को बचावकर्मियों के सामने चमत्कार तब हुआ जब एक परिवार के चार लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यह वायनाड का मुंडक्कई इलाका है, जहां बीते मंगलवार को भूस्खलन ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। रक्षा सूत्रों ने बताया कि केरल के वायनाड जिले के मुंडक्कई क्षेत्र में विनाशकारी भूस्खलन के तीन दिन बाद बचावकर्मियों ने शुक्रवार को पदवेट्टी कुन्नू के पास एक इलाके में चार लोगों के एक परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। मंगलवार को भीषण भूस्खलन की चपेट में आए वायनाड के मुंडक्कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव अभियान जारी है।

10 आईएएस के तबादले, मोहम्मद सुलेमान को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया

भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन सरकार ने शुक्रवार को 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नवीनपदस्थापना आदेश जारी किए। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है। वहीं, कृषि उत्पादन आयुक्त तथा परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे 1990 बैच के आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन मिश्रा को गृह विभाग का एसीएस बनाया गया है। परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार यथावत रखा है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे 1992 बैच के आईएएस अधिकारी केसी गुप्ता को लोक निर्माण विभाग का अपर मुख्य सचिव और संसदीय कार्य विभाग का प्रभार यथावत रखा है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव 1993 बैच के आईएएस अधिकारी संजय दुबे को प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बनाया गया है। आयुष विभाग तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव तथा राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी भोपाल का प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे 1993 बैच के आईएएस अनिरुद्ध मुकर्जी को मध्यप्रदेश भवन नई में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाया गया है।

दीपाली रस्तोगी को पंचायत एवं ग्रामीण विकासः सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव 1994 बैच की आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव 1996 बैच के आईएएस डीपी आहूजा को मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, आयुष विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का प्रमुख सचिव और मत्स्य महासंघ का प्रबंध संचालक और राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त 2000 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक पोरवाल को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव और राहत आयुक्त एवं पुर्वास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

संदीप यादव को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षाः विमानन तथा जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव और मध्यप्रदेश माध्यम के संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे 2000 बैच के आईएएस अधिकारी संदीप यादव को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव्र, गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रमुख सचिव, प्रवासी भारतीय विभाग का प्रमुख सचिव तथा स्वास्थ्य सेवाएं का आयुक्त एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जनसंपर्क आयुक्त 2006 बैच के आईआईएएस अधिकारी डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को जनसंपर्क विभाग का सचिव, जनसंपर्क आयुक्त के साथ ही मध्यप्रदेश माध्यम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सिटी चीफ
सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार
Fastest Growing Media Network
अवश्यकता है
इंदौर भोपाल जिले के सभी तहसीलो में दैनिक अख़बार और डिजिटल रिपोर्टर की।
डिजिटल और प्रिंट के लिये मार्केटिंग टीम (मेल/फीमेल) एवं हेल्परो की अवश्यकता हैं
डिजिटल मीडिया का क्रान्तिकारी कदम
डिजिटल भारत में खबरों के लिए देखे सिटी चीफ न्यूज़
रिपोर्टर बनने के लिए सम्पर्क करे
9755996590

सिंगल कॉलम

82 साल के बुजुर्ग से ठगी, डीआरपी कंपनी के संचालक ने 20 लाख ठगे

इंदौर। इंदौर की भंवरकुंआ पुलिस ने 82 साल के बुजुर्ग की शिकायत के मामले में डीआरपी कंपनी के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। बुजुर्ग से रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट के नाम पर आरोपी ने 20 लाख रुपए ठगे। इस मामले में रुपए नहीं देकर गार्ड से गोली मारने की धमकी बुजुर्ग को दी। बुजुर्ग ने थाने में शिकायत की। इसके बाद केस दर्ज किया गया। भंवरकुआ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ओमप्रकाश पुत्र ब्रजमोहन शर्मा निवासी नंदानगर की शिकायत पर शरद पुत्र दिनेश पोरवाल निवासी साठ फीट रोड़ आइडियल स्कूल के सामने द्वारकापुरी पर 420,406,294,506 भादवि की धारा में केस दर्ज किया है। ओमप्रकाश ने अपनी शिकायत में बताया कि सपना संगीता रोड़ पर शैल टॉवर में शरद पोरवाल डीआरपी इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाता है। 7 दिसंबर 2022 को ओमप्रकाश से शरद ने संपर्क किया। जिसमें उसने बताया कि वह डबल रूपए देने के साथ उसे कंपनी में लगाएगा। जिसमें लोगो को लोन दिया जाता है। लोन देने के बाद मार्केट से ज्यादा ब्याज आता है। जिसमें उन्हें भी प्रॉफिट मिलेगा। पुलिस ने इस मामले में बुजुर्ग ओमप्रकाश ने भरोसा करते हुए। अलग-अलग मद से रुपए दे दिए। बुजुर्ग ओमप्रकाश ने बताया कि उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी शरद को भरोसा करते हुए दी थी। जिसमें ना रुपए दिए गए और ना ही उनका ब्याज दिया गया। इसके बाद वह रुपए मांगने गए तो शरद ने कहा कि अगर आफिस पर आए तो गार्ड से गोली पड़वा देगा। इसके बाद बुजुर्ग ने अफसरों को शिकायत की। जिस पर जांच करते हुए केस दर्ज कर लिया गया।

जिला जेल में आज शनिदेव की कथा सुनाएंगे महामंडलेश्वर दादू महाराज

इंदौर। श्रावण मास के पवित्र माह में शनिदेव के दिन शनिवार को इंदौर जिले की जेल में प्रसिद्ध शनि साधक महामंडलेश्वर दादू महाराज कैदियों को शनि देव की कथा सुनाएंगे। इंदौर के इतिहास में पहला मौका है जब किसी जेल में धरती के सर्वोच्च न्यायाधीश शनि देव की कथा का आयोजन हो रहा है। दादू महाराज संस्थान के मीडिया प्रभारी राम मूंदड़ा ने बताया कि जेल अधीक्षक अलका सोनकर के प्रयासों से यह आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में 2000 कैदी शिरकत करेंगे। इस कथा में शनि देव की अनेक लीलाओं का वर्णन किया जायेगा। साथ ही, दादू महाराज सुखमय जीवन के लिए दिशा-निर्देश देंगे। वे कैदियों को अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने के सूत्र बताएंगे। आयोजन 3 अगस्त को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। संगीतमय कथा में भजन, शनि चालीसा, दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ और अंत में आरती की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि यह आयोजन जेल के कैदियों के जीवन में उन्हें एक नई शुरूआत करने का अवसर प्रदान करेगा।

सिरफिरे ने देसी कट्टे से किए फायर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

इंदौर। इंदौर के द्वारकापुरी में शुक्रवार शाम गोली चलने की वारदात हो गई। एक सिरफिरे ने देसी कट?टे से पहले अपने घर में फायर किया। इसके बाद उसने पड़ोसी पर गोली चला दी। द्वारकापुरी पुलिस मामले की जांच में जुटी। घटना गांधी चौक के पास आइडियल स्कूल के सामने की गली में हुई। यहां पर एक सिरफिरे मुकेश भारद्वाज ने शुक्रवार शाम एक के बाद एक दो फायर किए। जिसमें एक गोली अपने ही घर में चलाई। जबकि दूसरी पड़ोसी के ऊपर चला दी। आसपास के लोगों ने द्वारकापुरी पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से अवैध कट?टा बरामद किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी की दिमागी हालत ठीक नही है। वह गली में सभी से विवाद करता रहता है।

नगर निगम में बाउंसरों की तैनाती पर गरमाया विवाद

इंदौर। नगर निगम के बजट सम्मेलन में सदन में बाउंसर तैनात किए जाने का मुद्दा गरमाने लगा है। कांग्रेस पार्षदों ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई है। यह पहला मौका है जब निगम के सम्मेलन में बाउंसरों को तैनात किया गया। चार माह पहले रिमूवल गैंग को सेना की वर्दी से मिलती-जुलती ड्रेस पहनाने का भी पूर्व सैनिकों ने विरोध किया था। इसके बाद नगर निगम को वर्दी का फैसला वापस लेना पड़ा था। अब बाउंसर रखे जाने के मामले में नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं। सम्मेलन के दौरान गेट पर तैनात बाउंसरों ने तख्तियां लेकर सदन में जाने का प्रयास कर रहे कांग्रेस पार्षदों को गेट पर रोका था। पार्षदों का गेट पर बाउंसरों से विवाद भी हुआ था। आपको बता दें कि पांच साल पहले भी रिमूवल गैंग में कुछ कर्मचारी बाउंसर के रूप में रखे गए थे,जो काली टी शर्ट और जिंस पहनकर अफसरों के साथ तैनात रहते थे। उनका भी काफी विरोध हुआ था। फिर उन्हें गैंग से हटा दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि शहर के पब-बारों में बाउंसर तैनात रहते है, लेकिन निगम के सम्मेलन में बाउंसर तैनात कर भाजपा परिषद पब-बार की संस्कृति निगम में लाना चाहती है। जनप्रतिनिधियों को रोकने के लिए नगर निगम ने किस नियम के तहत अफसरों ने बाउंसर रखे है।

100 वर्ष पूरे करने पर कोई बड़ा आयोजन और उत्सव नहीं करेगा आरएसएस

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले साल 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर संघ की तरफ से बड़ा आयोजन या उत्सव नहीं किया जाएगा,बल्कि संघ को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। इंदौर में संघ के संपर्क विभाग की बैठक में यह तय हुआ है कि संघ ज्यादा से ज्यादा सामाजिक, धार्मिक आयोजनों में सहभागिता बढ़ाए और समाज को जागरुक करने का काम करें। बैठक में यह भी कहा गया कि जो लोग संघ से ज्यादा वाकिफ नहीं है, लेकिन संघ के प्रति गलत धारणा रखते हैं, संघ कार्य और विचारधारा से अवगत कराकर उन लोगों की धारणा दूर कैसे की जा सकती है, इस पर ध्यान देने की जरुरत है। बैठक में सरकार्यवाह दतात्रय होसबोले ने भी भाग लिया। उन्होंने भी एक सत्र में पदाधिकारियों को संबोधित किया और देश की सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक शक्तियों को मजबूत करने पर बल दिया। सोशल इंजीनियरिंग के जरिये समाज के हर तबके तक संघ की पैठ बनाने की बात भी कही गई।

180 से ज्यादा पदाधिकारी आए

इस बैठक में देशभर से 180 से ज्यादा पदाधिकारी आए हुए है। 3 व 4 अगस्त को संपर्क विभाग की बैठक एमआर-10 के एचआर ग्रीन रिसोर्ट में होगी। अगले साल आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होंगे,लेकिन तय हुआ है कि संघ शताब्दी दिवस

धूमधाम से नहीं मनाएगा, बल्कि सेवा कार्यों किए जाएंगे।

सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है संघ

आरएसएस सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। युवा वर्ग तक संघ अपनी विचारधारा, संघ कार्य की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगा। जनवरी में हुए अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय संपर्क विभाग ने देशभर में हिन्दू समाज को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज को जोड़े रखने और विचारधारा को आमजनों तक फैलाने के लिए संघ से जुड़े संगठनों की गतिविधियां बढ़ाने पर भी बैठक में जोर दिया गया।

संघ के संपर्क विभाग का बीते दो दशक में काम काफी फैल चुका है। कभी इसे लूप लाईन भी कह दिया जाता था, क्योंकि महत्वपूर्ण दायित्व से मुक्त हुए पदाधिकारियों को इस विभाग में जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, लेकिन दो दशक में यह बात पूरी तरह से मिथक साबित हो चुकी है। विभाग का सीधा समाज के हर वर्ग से संपर्क होता है। संघ के कामकाज, विभिन्न प्रकल्प को लेकर लोगों की राय, विजयादशमी पर संघ प्रमुख के भाषण पर प्रतिक्रिया जुटाने जैसे काम विभाग के हैं। इन्ही जानकारियों के आधार पर आगामी कार्ययोजना तैयार की जाती है। संपर्क विभाग ने अब अपनी पैठ समाज के प्रबुद्ध वर्ग में बढ़ाना शुरू कर दिया है। बीते दो दशक में डॉक्टर्स, एडव्होकेट, इंजीनियर्स, आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों पर खूब ध्यान लगाया। इसके परिणाम भी सार्थक हुए। अब विभाग का सारा फोकस ब्यूरोकेट, प्रोफेशनल्स और युवाओं पर रहेगा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इस बैठक में आरएसएस की रचना के अनुरूप बने सभी प्रांत के संपर्क व सह संपर्क प्रमुख शामिल हुए। बैठक में समस्त बाहरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी स्थानीय पदाधिकारियों के हाथ में रही। बैठक स्थल पर ओर उसके आसपास के क्षेत्र में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। बैठक स्थल पर बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहा। पुलिस बल को भी एक सीमा तक ही सिमित रखा गया।

एआईसीटीएसएल की बोर्ड बैठक में लिए गए बड़े फैसले

इंदौर को मिलेंगी 150 इलेक्ट्रिक बसें

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। एआईसीटीएसएल की बोर्ड बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में कई बड़े निर्णय लिए गए। बोर्ड द्वारा ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। महापौर ने बताया कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अंतर्गत भविष्य में 150 मिडी इलेक्ट्रिक बसों को सौगात जल्द ही शहर को मिलेगी। इन बसों के डिपो एवं चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था चंदन नगर एवं नायता मुंडला में होगी। भविष्य में दस इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों का भी संचालन किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। इसमें इंदौर दर्शन के लिए भी बस संचालित होगी। यह भी बताया गया कि भविष्य में लास्ट माइल कनेक्टिविटी एवं ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही पीपीपी मॉडल पर निविदा आमंत्रित कर इलेक्ट्रिक बाइक का संचालन किया जाएगा।

स्क्रैप बसों का इस्तेमाल स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट स्कूल के लिए होगा

बैठक में बताया गया कि स्क्रैप बसों की ई-नीलामी की जाएगी एवं स्क्रैप बसों का उपयोग स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट स्कूल जैसी योजनाओं हेतु किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एप बेस्ड टैक्सी सर्विस निविदा आमंत्रित कर जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। बैठक में शहर में संचालित बसों (सिटी बस, आई बस एवं ई बस) के किराए का पुनरीक्षण किया गया। इसमें

निर्णय लिया कि ई बाइक (माय बाइक) के किराए में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में बस संचालन संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में एआईसीटीएसएल बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं संभागायुक्त दीपक सिंह, निदेशक एवं कलेक्टर आशीष सिंह, प्रबंध निदेशक एवं निगमायुक्त शिवम वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अपर आयुक्त मनोज पाठक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सुगम यातायात के लिए विशेष प्रयास

इंदौर में सुगम यातायात के लिए विशेष प्रयास जारी हैं। इसके तहत शहर में विभिन्न जगहों पर फ्लाईओवर, ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। इन कार्यों को गति देने के संबंध में चर्चा के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने विभिन्न फ्लाईओवर, ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर के संबंध में कराए गए फिजिबिलिटी सर्वे की उपयोगिता के संबंध में चर्चा की। बताया गया कि इन कार्यों के संबंध में सभी पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों से व्यापक विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।

फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों पर चर्चा

बैठक में शहर में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों के संबंध में भी चर्चा की गई। संबंधित निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे की यातायात प्रभावित नहीं हो। वाहन चालकों को परेशानी नहीं हो। बारिश को देखते हुए जल निकासी के समुचित इंतजाम करें। गड्ढों का भी भराव करें।

ड्रेनेज घोटाले में फरार 8 आरोपितों पर पुलिस ने रखा इनाम

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर नगर निगम के चर्चित डेढ़ सौ करोड़ के ड्रेनेज घोटाले में चौंकाने वाला राजफाश हुआ है। पुलिस ने महिला ऑडिटर सहित आठ को आरोपित माना है। सभी अफसर गिरफ्तारी के डर से घरों से गायब हो गए हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा कर संपत्ति की जानकारी जुटाने में लगी है।बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की भी जांच की जा रही है। ड्रेनेज घोटाले में पहला केस 16 अप्रैल को राहुल बढेरा, रेणु बढेरा, जाकिर खान, सिद्दीकी खान और सादिक के खिलाफ दर्ज हुआ था। इसके बाद परतें खुलती गई और नगर निगम के अधिकारियों ने सात अपराध दर्ज करवाए। विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस ने पांच प्रकरणों में चालान पेश कर दिया। हालांकि, इन प्रकरणों में विवेचना आगे भी जारी रखी है। चालान में ऑडिटर सौम्या शुक्ला, पूनम चतुर्वेदी, जगतसिंह औरिया, अरुण शुक्ला, मुकेश श्रीवास्तव, शरद कतरोलिया, विक्रम वर्मा और जगदीश चौकसे को भी आरोपित बनाया गया है। इनके विरुद्ध मुलजिमों ने बयान दर्ज करवाए हैं। जानकारी मिलने के बाद सभी आरोपित घरों से गायब हो गए हैं। टीआई सिसोदिया के मुताबिक, जांच के दौरान पता चला कि आरोपितों की ठेकेदार राहुल बढ़ेरा, रेणु बढ़ेरा, जाकिर खान, मोहम्मद सिद्दीकी से सांठगाठ थी। अफसरों ने मिलीभगत कर बिल पास किए थे। आरोपितों ने तुलसी नगर, नंदानगर, द्रविड़ नगर सहित अन्य कालोनियों में चेंबर बनाने, गड्ढे और लाइन खोदना बताकर बिल जमा किए थे। अफसरों ने एक ही दिन में आरोपितों के बिल पास कर फाइल भुगतान के लिए अकाउंट शाखा में भेज दी। आरोपितों ने एक दिन में 500 से ज्यादा चेंबर बनाना, 500 से ज्यादा गड्ढे और पांच किमी तक की लाइन खोदना बताया था। ऑडिटर ने मिलीभगत कर एक दिन में बिल पास कर दिए। टीआई के मुताबिक, ड्रेनेज और ट्रेंचिंग घोटाले के संबंध में कुल सात प्रकरण दर्ज हुए हैं। पुलिस इस मामले में राहुल बढेरा, रेणु बढेरा, जाकिर, सिद्दीकी, साजिद, इमरान, मौसम व्यास, राजेंद्र शर्मा, उदय सिंह, चेतन सिंह, अभयसिंह राठौर, राजकुमार सालवी और ऑडिटर समरसिंह परमार, अनिल गर्ग, रामेश्वर, मुरलीधरन के विरुद्ध चालान पेश कर चुकी है। मामले में अभय राठौर को मास्टरमाइंड बताया गया है।

मध्यपूर्व में बढ़ा तनाव, इंदौर में सोने का भाव 72 हजार के पार

इंदौर। अमेरिकी फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दरों में कटौती करेगा और बाजार इसे तय मान रहा है। दूसरी ओर मध्यपूर्व में बढ़े तनाव के कारण अमेरिका के शेयर बाजार के साथ ही भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। इसके चलते निवेशकों की कीमती-धातुओं में खरीदी बढ़ गई है। कॉमेक्स पर सोना वायदा 10 डॉलर बढ़कर 2468 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। इसके असर से इंदौर मार्केट में भी सोने की कीमतों में बढ़त जारी रही। शुक्रवार को इंदौर में सोना केडबरी नकद में 400 रुपए बढ़कर एक बार फिर 72 हजार के पार 72200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आरटीजीएस में भी सोना 72200 रुपये बोला गया। कॉमेक्स पर चांदी वायदा में कोराबार सुस्त होने के कारण 16 सेंट घट कर 28.99 डॉलर प्रति औंस रह गई। हालांकि भारतीय बाजारों में चांदी का स्टाक सुगम नहीं होने के कारण कीमतें स्थिर रही। चांदी चौरसा 85400 रुपये प्रति किलो बोली गई। ज्वेलर्स का मानना है कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड निचले स्तर पर जाने के कारण भी सोने को सपोर्ट मिल रहा है।

कॉलेज लेवल काउंसलिंग का तीसरा चरण शुरू, यूजी-पीजी में प्रवेश का मौका

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश को लेकर तीन महीने से काउंसिलिंग चल रही है। बावजूद इसके कॉलेजों में तीस फीसदी सीटें खाली हैं। इसके पीछे असल वजह यह है कि सीयूईटी रिजल्ट में देरी होने से विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश नहीं ले रहे थे। चार दिन पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परिणाम घोषित किया है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सहित अन्य यूजी कोर्स में प्रवेश की संख्या बढ़ सकती है। ऐसा ही हाल स्नातकोत्तर में देखने को मिला है, क्योंकि स्नातक अंतिम वर्ष में फेल विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा नहीं हुई है। इसके चलते स्नातकोत्तर में भी प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या कम है। अब उच्च शिक्षा विभाग ने रिक्त सीटों को भरने के लिए कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) का अतिरिक्त चरण रखा है। विभाग ने काउंसिलिंग शेड्यूल गुरुवार रात में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। प्रदेशभर के सरकारी और निजी कॉलेजों में रिक्त सीटों पर प्रवेश देने के लिए सीएलसी का तीसरा चरण रखा है। मौजूदगा स्थित के मुताबिक दो लाख यूजी और डेढ़ लाख पीजी में सीटें खाली है। इन पर आवेदन के लिए आज विभाग ने पंजीयन शुरू कर दिया है। विद्यार्थियों को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंसदीदा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करना है। 5 अगस्त तक पंजीयन को लेकर समय दिया है। दस्तावेजों के सत्यापन भी 5 अगस्त तक होंगे। अधिकारियों के मुताबिक सीएलसी में पंजीयन सिर्फ वही छात्र-छात्राएं कर सकते है, जिन्होंने पूर्व में काउंसिलिंग को लेकर आवेदन नहीं किया है। वहीं पूर्व में पंजीयन करवाने वाले विद्यार्थियों को सीधे च्वाइंस फीलिंग के माध्यम से पसंदीदा कॉलेज बताना है। 7 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभाग मेरिट बनाएगा। फिर छात्र-छात्राओं को सीटें आवंटित की जाएगी। यह सूची 7 अगस्त को जारी होगी। फिर विद्यार्थियों को चार दिनों के भीतर फीस जमा करना है। 10 अगस्त तक फीस भरने की समयावधि निर्धारित की गई है।

सिस्टम से परेशान हुआ तो दे डाली आईआईटी में ब्लास्ट की धमकी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। सिस्टम से परेशान एक आम शख्स किस हद तक जा सकता है, इसका ताजा उदाहरण इंदौर में देखने को मिला। नौकरी नहीं मिलने से नाराज एक युवक ने आईआईटी कैंपस स्थित केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देकर पूरे सिस्टम को हिला डाला था। दो हफ्ते का समय लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। आरोपी कंम्प्यूटर एप्लीकेशन का पोस्ट ग्रेजुएट है। आरोपी है बड़नगर का रहने वाला चेतन सोनी। चेतन डीएवीवी के 2015 बैच का एमसीए है। वह लगातार नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन हर जगह पहुंच और जैक वालों को ही नौकरी मिलने की वजह से वह परेशान था। पिछले महीने वह इंदौर के आईआईटी कैंपस के केंद्रीय विद्यालय ने कम्प्यूटर लैब टेक्नीशियन की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चेतन इंटरव्यू के लिए बैठा रहा। इंटरव्यू के लिए उसका 12वां नंबर था। उसके आगे एक लड़की का नंबर था। वह चेतन जितनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला पैनल उससे हंस-हंसकर बाते कर रहा था। इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे चौकीदार ने उससे कहा कि इसका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद ही कॉमन मैन की खोपड़ी खिसक गई और उसने सिस्टम को सबक सिखाने की खतरनाक योजना बना डाली।

पुलिस ने किया मामले का खुलासा

20 जुलाई को इंदौर के आईआईटी कैंपस स्थित केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के 15 अगस्त को स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई मेल मिला था। इसमें पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी जिक्र किया गया था। इसकी जानकारी प्रिंसिपल ने फौरन आईआईटी प्रबंधन के साथ ही सिमरोल पुलिस को दी। पाकिस्तान और आईएसआई का नाम आने के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई। मुख्यालय से पुलिस फोर्स के साथ फौरन बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड की टीम को भेजा गया। पूरे कैंपस की जांच की गई, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला।

धमकी भरा ई मेल भेजने की बात कबूल की

पुलिस ने धमकी देने वाले की तलाश शुरू की। लगभग 2 हफ्ते की मेहनत के बाद टेक्निकल आधार पर पुलिस आरोपी चेतन सोनी तक पहुंच गई। पूछताछ में उसने धमकी भरा ई मेल भेजने की बात कबूल की। सिस्टम से परेशान होकर बम ब्लास्ट की धमकी देने के इस मामले से ए वेडनसडे फिल्म की याद आ गई। उसमें भी आतंकवादियों को सजा नहीं मिलने से परेशान एक आम आदमी कोरी धमकियों से पूरे सिस्टम को हिला देता है। फिल्म में अंत में आरोपी पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में आरोपी कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सका।

मप्र में सामान्य से 12 फीसदी ज्यादा बारिश

नदी-नाले उफान पर, 26 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी

सिटी चीफ भोपाल।

दो-तीन दिन की सुस्ती के बाद प्रदेश में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। भोपाल, सीधी, नर्मदापुरम, रायसेन समेत कई शहर बारिश से तरबतर हैं। पश्चिम बंगाल के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा अलग-अलग स्थानों पर चार मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इस सीजन में एक जून से लेकर दो अगस्त की सुबह साढ़े आठ बजे तक 524.9 मिमी. वर्षा हो चुकी है। जो सामान्य वर्षा (470.5 मिमी.) की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। इसमें पूर्वी मध्य प्रदेश में अब तक 537.7 मिमी. वर्षा हुई। जो सामान्य वर्षा (514.8 मिमी.) के मुकाबले चार प्रतिशत अधिक है। पश्चिमी मप्र में अभी तक 515.1 मिमी. वर्षा हुई है। जो सामान्य वर्षा (436.5 मिमी.) के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है।

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंदसौर, शहडोल, सागर, उमरिया और रायसेन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बालाघाट, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पन्ना, निवाड़ी, रीवा, सिवनी, सीधी, मऊगंज, बैतूल, देवास, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा और

पांढुर्ना जिलों में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा छतरपुर, निवाड़ी, सागर, सतना, टीकमगढ़, मैहर, आलीराजपुर, अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, गुना, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंदसौर , नीमच, राजगढ़, शाजापुर, शिवपुरी और श्योपुरकलां जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलीं

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले चौबीस घंटों के दौरान सीधी में 91.8, नर्मदापुरम में 90.4, पचमढ़ी में 86.2, भोपाल में 85.2, रायसेन में 79.4, सिवनी में 32.2, छिंदवाड़ा में 25.8, उज्जैन में 18.6, मलाजखंड में 16.8, धार में 16.3, रतलाम में 16, खरगोन में 15.8, रीवा में 14.4, उमरिया में 12.2, खंडवा में 12, गुना में 11.4, जबलपुर में 7.3, मंडला में 6.8, बैतूल का क्षेत्र बन गया है। इससे संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। इसके पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

मानसून द्रोणिका अब श्रीगंगानगर, हिसार, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, डाल्टनगंज, गांगेय पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड पर कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र से होकर दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक फैली है। पूर्वोत्तर राजस्थान और आसपास के इलाकों पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

पंजाब और आसपास के इलाकों पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

दक्षिण गुजरात से केरल तट तक औसत समुद्र तल पर अपतटीय द्रोणिका बनी हुई है। पूर्वोत्तर अरब सागर और उससे सटे सौराष्ट्र के ऊपर समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। बारिश के बाद अशोक गार्डन थाना, 80 फिट रोड से सेमरा जाने के लिए जो मेन रोड उसकी स्थिति बदतर हो गई है। ये वार्ड 38 के हाल हैं। जहां सड़क पहले से गड्ढों में तब्दील है। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। राहगीरों को हर कदम पर परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही यहां के लोगों का कहना है की बारिश होने के बाद कुछ ही देर में सड़को में घुटनों तक पानी भर जता है। और आए दीन दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके अलावा काजी कैंप, बैरागढ़, ऐशबाग, भारत टॉकीज आदि की सड़कों की भी हालत खराब है।

वे वेदर सिस्टम सक्रिय

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उससे सटे बांग्लादेश पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में गांगेय पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड पर एक कम दबाव एवं खजुराहो में 6.6, इंदौर में 5.9, दमोह में पांच, ग्वालियर में 2.4 एवं सागर में 2.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस दौरान पचमढ़ी में अधिकतम 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलीं।

सिंधी कॉलोनी चौराहे पर वाहन चालक होते रहे परेशान

पुराने भोपाल के सिंधी कॉलोनी चौराहे पर पिछले 30 घंटे से सड़क पर 1 फीट पानी भरा हुआ है। इसके चलते यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को तो परेशान होना ही पड़ रहा है, उनके अलावा सड़क किनारे बने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह अस्पताल के ठीक सामने सड़क पर एक फिट पानी जमा होना है।

नादरा बस स्टैंड की हालत खराब

नादरा बस स्टैंड से स्टेशन जाने वाली सड़क पर गाड़ी की आवाजाही इक्का दुक्का ही रही, यहां पर करीब 2 फीट से अधिक पानी सड़क पर भरा था, जिसमें अधिकतर भारी वाहन ही गुजरते नजर आए, इसके अलावा नादरा बस स्टैंड के सामने भी पानी भर गया।

आयुष और स्वास्थ्य विभाग के बीच सामंजस्य नहीं बनने से आ रही परेशानी

प्रदेश के 10 हजार स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं मिल रहा आयुर्वेदिक इलाज

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। प्रदेश में आयुष और स्वास्थ्य विभाग के बीच सामंजस्य नहीं बन पाने के चलते करीब 10 हजार स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुर्वेद इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार ने प्रदेश में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुर्वेद पद्धति से उपचार करने के निर्देश दिए थे लेकिन वर्ष भर बाद भी इस पर जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जा सका है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथी पद्धति से उपचार चल रहा है। जबकि देश के अन्य राज्यों राजस्थान, त्रिपुरा और हरियाणा में आयुर्वेद से उपचार भी शुरू हो चुका है वहीं पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ की सरकारों ने आदेश निकाल दिए हैं।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेद से

उपचार करने के लिए 1100 कम्युनिटी हेल्थ आफिसर्स (सीएचओ) की नियुक्ति विभाग कर चुका है। इन्हें आयुर्वेद में उपचार का अच्छा अनुभव है। क्योंकि इन्होंने बीएएमएस (बैचलर आफ आयुर्वेद मेडिसिन इन सर्जरी) में डिग्री भी प्राप्त की है। नियुक्ति के बाद इन्हें छह माह का एलोपैथी प्रशिक्षण दिया गया था। ताकि नियुक्त यह सामुदायिक अधिकारी दोनों ही विद्याओं में बेहतर सेवाएं दे सकें।

यहां से सीएमएचओ लिख चुके हैं पत्र

डिंडोरी, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली से सीएमएचओ एनआरएचएम को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन आयुर्वेद उपचार शुरू नहीं करवाया गया है। उप संचालक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एनएचएम मनीष सिंह का कहना है कि अगर आयुष विभाग के डॉ. आयुर्वेद में उपचार करना चाहते हैं तो वह स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामंजस्य बनाकर लोगों का उपचार कर सकते है। इसके निर्देश दिए जा चुके हैं।

एलोपैथी में महंगे इलाज के कारण जरूरी है आयुर्वेदिक

बता दें कि 26 जुलाई 2023 को भारत सरकार में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक एलएस चांगसन ने इस संदर्भ में राज्यों को पत्र लिखा था। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को जो आदेश जारी किया था उसके पीछे कई कारण थे।

डिप्टी सीएम को मिल सकते हैं एक से ज्यादा जिले

इस सप्ताह तय होंगे मंत्रियों के जिला प्रभार

सिटी चीफ भोपाल।

स्वतंत्रता दिवस परेड की सलामी और प्रदेश में होने वाले कर्मचारियों के तबादलों की जिम्मेदारी जिलों का प्रभार देखने वाले मंत्री ही संभालेंगे। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। मंत्रियों के प्रभार जिलों की सूची तैयार कर ली गई है। जल्दी ही इसका एलान किया जा सकता है।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इसका एलान संभवतः इसी सप्ताह में कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि तय किए गए फार्मू:ले के मुताबिक डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को एक से अधिक जिले की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी तरह प्रदेश के कद्दावर मंत्रियों को भी बड़े जिलों की कमान देने की तैयारी की जा रही है।

गौतलब है कि अधिकांश मंत्री

इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर जैसे जिलों का प्रभार चाहते हैं। इसी कशमकश में सूची को अंतिम रूप देने में अधिक समय लग गया है। बताया जा रहा है कि इसको फाइनल करने के लिए दिल्ली नेतृत्व से भी सहमति ली गई है। इसी माह खुलने वाले ट्रांसफर बैन के मद्देनजर भी मंत्रियों को जिला प्रभार दिए जाने की कवायद तेज है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारी अधिकारियों के तबादले जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही किए जाएंगे। जिलों में होने वाले स्थानांतरण में इन जिला प्रभारी मंत्रियों की अहम भूमिका रहने वाली है। इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर होने वाले झंडा वंदन कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे। यहां इन्हीं के हाथों झंडा फहराया जाएगा। इस मौके पर होने वाली परेड की सलामी भी प्रभारी मंत्री ही लेंगे।

बदले की नीयत से किशोर को उतारा मौत के घाट

सिटी चीफ भोपाल।

टीटी नगर इलाके की अर्जुन नगर बस्ती में गुरुवार की रात एक किशोर की हत्या कर दी गई। दिन में किशोर का मोहल्ले के एक युवक से झगड़ा हुआ था। इस दौरान किशोर ने युवक को पत्थर मार दिया था। इसी बात का बदला लेने के लिए युवक ने रात में किशोर पर धारदार चीज से हमला कर दिया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टीटी नगर थाना प्रभारी मनोज पटवा ने बताया कि 16 वर्षीय किशोर ब्रजकांत पांडे अर्जुन नगर में बस्ती में रहता था। इसी बस्ती में सोनू बाथम नाम का युवक रहता है। सोनू बदमाश प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ पूर्व से ही 4-5 अपराध दर्ज हैं। इधर ब्रजकांत के खिलाफ भी पूर्व में अड़ीबाजी का मामला दर्ज हो चुका था। दोनों ही मोहल्ले में अपनी धौंस जमाना चाहते थे। इसी बात को लेकर उनके बीच रंजिश चलती रहती थी। गुरुवार की दोपहर ब्रजकांत और सोनू के बीच विवाद हो गया। झगड़े के दौरान ब्रजकांत ने सोनू को पत्थर मार दिया था। उनके बीच में विवाद बढ़ता इससे पहले ही अन्य युवकों ने बीच-बचाव कर मामले को शांत कर दिया था। सोनू ने तभी से ब्रजकांत को सबक सिखाने का मन बना लिया। रात करीब साढ़े दस बजे ब्रजकांत अपने घर के पास ही खड़ा था। इसी दौरान सोनू वहां पर आया तथा उसने ब्रजकांत पर धारदार चीज से हमला कर दिया। हमला करने के बाद वह मौके से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

एमपी नगर थाना क्षेत्र में वारदात, बैंक से पैसे निकालने के बाद युवक को बनाया निशाना

युवक से दिनदहाड़े पांच लाख की लूट

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल में दिनदहाड़े पांच लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जब एक युवक बैंक से पैसे निकालकर अपनी दुकान जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घटना एमपी नगर थाना क्षेत्र के कीलनदेव टावर चौराहे के पास की है। 18 वर्षीय अहमद के पिता अब्दुल सत्तार का मार्बल का कारोबार है। वह मालवीय नगर में रहते है। एक ग्राहक ने उनको मार्बल का 5 लाख 25 हजार रुपए का चेक से पेमेंट किया था।

शुक्रवार को अहमद को पिता ने पेमेंट निकालने बैंक भेजा था। वह बैंक से पैसा निकालकर अपनी स्कूटी से कीलनदेव चौराहे पास पहुंचे। तभी पीछे से बाइक सवार बदमाशों ने उनको टक्कर मारी और चाकू से पीठ पर वारकर पैसों से भरा बैंक छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों का कोई सुराग मिल सके।

भाजपा अध्यक्ष ने संसद में कहा-बुन्देलखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का संकट, एम्स की स्थापना हो

वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो में 30 बेड का अस्पताल नहीं

सिटी चीफ भोपाल।

लोकसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बुन्देलखंड क्षेत्र में अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने का मामला उठाया। स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा मैं बुन्देलखंड क्षेत्र में खजुराहो से सांसद हूं। बुन्देलखंड का संपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से पीछे है। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है पीएम जी की आईकोनिक सिटी है। वहां पर 30 बिस्तर का अस्पताल ना होने से विदेशी पर्यटकों को परेशानी होती है। वीडी ने खजुराहो संसदीय क्षेत्र में एम्स की स्थापना करने की मांग रखी। वीडी शर्मा ने कहा- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बुन्देलखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत की दृष्टि से स्वास्थ्य की सुविधाओं में घनत्व बहुत कम है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हों या अन्य स्वास्थ्य के केन्द्र हों उनके बारे में चिंता व्यक्त की गई है। बुन्देलखंड क्षेत्र में 500 किलोमीटर तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में रेफरल स्वास्थ्य सेवाएं भी लगभग नगण्य हैं। इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए भोपाल, इंदौर नागपुर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस क्षेत्र के लोगों को

परेशानी का सामना करना पड़ता है।

खजुराहो संसदीय क्षेत्र के तीन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं

वीडी शर्मा ने कहा- मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में तीन जिले आते हैं। इन तीनों जिलों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। बुन्देलखंड क्षेत्र में यूपी का हिस्सा भी आता है। सागर दतिया और झांसी में मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन बाकी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज ना होने से परेशानी आ रही है। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है पीएम की आईकोनिक सिटी है। वहां पर 30 बिस्तर का अस्पताल ना होने से विदेशी पर्यटकों को परेशानी होती है। जी-20 की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से खजुराहो में हुई। एम्स की सुविधा जो देश के अन्य क्षेत्रों में मिल रही है। बुन्देलखंड क्षेत्र के खजुराहो जहां एयर कनेक्टिविटी है।रोड कनेक्टिविटी भी है। बुन्देलखंड में एम्स की सुविधा हो तो लोगों को मदद मिल सकेगी।

योगा नेचुरोपैथी का ऑल इंडिया सेंटर स्थापित किया जाए

वीडी ने कहा- खजुराहो क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेजों को सुविधा मिलती है। बुन्देलखंड के अस्पतालों में आयुष्मान योजना से वैसी सुविधा दी जाए। खजुराहो में सांस्कृतिक और अध्यात्म का केन्द्र है। जीरो पॉल्यूशन का क्षेत्र है। प्राकृतिक क्षेत्र होने के कारण खजुराहो में योग और नेचुरोपैथी का ऑल इंडिया सेंटर खुलने का प्रस्ताव है। ऑल इंडिया का सेंटर बने या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए।

सम्पादकीय

लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी से मिलेगी राहत?

करों का अधिक बोझ बीमा विस्तार से जुड़ी नीतियों को प्रोत्साहित करने की सोच के विरुद्ध है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन की तमाम अनिश्चितताओं के चलते अपनी व परिवार की सुरक्षा हेतु चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन व सेहत बीमा के प्रीमियम पर टैक्स लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा ही है।

आज के समय में शायद ही ऐसा कोई होगा जो लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और मेडिकल इंश्योरेंस यानी इलाज का बीमा से अनजान हो। नियमित अंतराल पर तय प्रीमियम जमा करने के इसके जरिये हमें लाइफ और हेल्थ का इंश्योरेंस कवर मिलता है। सरकार की ओर से इस पर टैक्स भी लगाया जाता है, क्योंकि सरकारी तौर पर इसे फाइनेंशियल सर्विस माना जाता है। इसलिए दोनों ही तरह का इंश्योरेंस जीएसटी के दायरे में आता है। लेकिन इन दिनों लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार से लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाला जीएसटी वापस लेने की मांग ही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में गडकरी ने कहा कि इस कदम से बीमा कंपनियों पर टैक्स का बोझ होगा और देश में महत्वपूर्ण बीमा उत्पादों की मांग को बढ़ावा मिलेगा। नागपुर एलआईसी यूनियन की ओर से सीतारमण को पत्र लिखते हुए गडकरी ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगाया जाने वाला इनडायरेक्ट टैक्स जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। अभी लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। इस बीच, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इस बात पर खुशी जताई कि गडकरी ने वित्तमंत्री से बीमा पर जीएसटी हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने भी यही सुझाव दिया था। चिदंबरम ने कहा कि गडकरी ने मेरी उस मांग का समर्थन किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे लोगों की अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बता दें कि गडकरी की मांग का कई विपक्षी नेताओं ने समर्थन किया है। दरअसल इस प्रासंगिक मुद्दे को उठाकर गडकरी ने करों के मानवीय पक्ष को ही उजागर किया है। निस्संदेह, जीएसटी को कम करना एक मानवीय पहल होगी। वह भी उस देश में जहां 73 फीसदी लोगों के पास चिकित्सा बीमा नहीं है। ऐसे में बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगाना क्या न्यायसंगत होगा? दरअसल, महंगे प्रीमियम व उस पर लगने वाले करों के चलते करीब पच्चीस से तीस फीसदी लोग हर साल अपने चिकित्सा बीमा का नवीनीकरण नहीं कर पाते। निस्संदेह, गडकरी ने बीमा धारकों की दुखती रग पर हाथ रखा है। यह विडंबना ही है कि भविष्य में जीवन की अनिश्चितताओं से मुक्ति व अपने तथा परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा चाहने वाले व्यक्ति पर करों का अनुचित बोझ डाला जाता है। जाहिर है कि करों का अधिक बोझ बीमा विस्तार से जुड़ी नीतियों को प्रोत्साहित करने की सोच के विरुद्ध है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन की तमाम अनिश्चितताओं के चलते अपनी व परिवार की सुरक्षा हेतु चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन व सेहत बीमा के प्रीमियम पर टैक्स लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा ही है। वैसे भी जीवन के उत्तरार्ध में तमाम चिकित्सा समस्याओं से जूझने वाले बुजुर्गों के लिए यह जीएसटी चुकाना एक अन्याय जैसा ही है क्योंकि इनमें से अधिकांश की यह सेवानिवृत्ति की उम्र होती है। इस उम्र तक आते-आते उसके आय के स्रोत सिकुड़ने लगते हैं। वे अपने बच्चों पर आश्रित होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीवन के जोखिम के लिए बीमा कराने वाले व्यक्ति के प्रीमियम पर अधिक कर लगाना एक तरह से बेबात का जुर्माना वसूलने जैसा है। खासकर समाज में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तो यह कर बेहद परेशान करने वाला ही है, जो जैसे-तैसे प्रीमियम के लिये पैसा जुटाने का उपक्रम करते हैं। यह भी एक हकीकत है कि ज्यादा कर लगाने से बीमा उत्पादों का दायरा बढ़ाने के तमाम प्रयास निरर्थक ही सिद्ध होते हैं। यही वजह है कि देश का बीमा उद्योग लंबे समय से अपने उत्पादों की अपील बढ़ाने के लिए जीएसटी में कटौती की वकालत करता रहा है। यह बात स्पष्ट है कि सेहत व जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर कम करने से न केवल बीमा करवाना अधिक किफायती हो जाएगा, बल्कि इसके प्रसार को भी अपेक्षित बढ़ावा मिलेगा। सही मायनों में इससे व्यापक वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार में मदद मिलेगी। इससे नए उपभोक्ता बीमे के दायरे में लाए जा सकेंगे। बीमा कंपनियां जीएसटी कम होने पर नए उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकती हैं। दरअसल, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीएआई के वर्ष 2022-23 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीवन बीमा की भागीदारी महज 3.2 फीसदी व स्वास्थ्य बीमा की भागीदारी 0.94 फीसदी है।

आरक्षण की कहानी में डेढ़ सौ साल बाद नया मोड़

एससी/ एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है, लेकिन ज्यादातर हल्को में इस फैसले का स्वागत हुआ है, क्योंकि देश में आरक्षण की जो कहानी 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी, करीब डेढ़ सौ साल बाद इसमें एक नया और निर्णायक मोड़ आ गया है।

देश में एससी/ एसटी (अनुसूचित जाति/ जनजाति) वर्ग में भी उप श्रेणी यानी कोटे में कोटा को मंजूरी और इन दोनों आरक्षित श्रेणियों में भी ओबीसी की तर्ज पर क्रीमी लेयर तय करने के सुप्रीम को 6-1 के बहुमत से दिए फैसले के दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है, लेकिन ज्यादातर हल्को में इस फैसले का स्वागत हुआ है, क्योंकि देश में आरक्षण की जो कहानी 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी, करीब डेढ़ सौ साल बाद इसमें एक नया और निर्णायक मोड़ आ गया है।

आजादी के बाद 70 सालों से सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की लाभार्थी जातियों के भीतर से आवाज उठने लगी थी कि आरक्षण का फायदा भी समान रूप से सभी जातियों को नहीं मिल रहा है। लिहाजा इस लाभ का वितरण नए और न्यायसंगत तरीके किया जाए।

दूसरे शब्दों में कहें तो आरक्षण का लाभ उठाकर आर्थिक व सामाजिक बेहतरी हासिल करने वाला एक नए किस्म का 'ब्राह्मणवाद' इन जाति वर्गों में भी आकार लेने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामाजिक न्याय के इसी आलोक में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षित वर्ग के भीतर ही हितों के इस टकराव को लंबे समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य अपने यहां आरक्षित श्रेणियों में अधिक लाभान्वित और कम लाभान्वित जातियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। हालांकि यह काम बहुत सावधानी और पारदर्शिता से करना होगा। इसके लिए सही आंकड़े जुटाने होंगे। केवल वोटों की गोलबंदी के बजाए आरक्षण के समान वितरण की समुचित प्रक्रिया अपनानी होगी।

इस फैसले का विरोध जिन हल्कों से हो रहा है अथवा होगा, वे मुख्यत- वो जातियां हैं, जिन्हें आरक्षण का तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभ मिला है। कई जगह तो यह अब पीढ़ीगत रूप में भी बदल गया है।

दरअसल 'ब्राह्मणवाद' का सबसे बड़ा दोष भी उसका जन्मगत होना ही है। पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण ने भी इसी प्रवृत्ति को आरक्षित वर्ग में पनपाया है। आरक्षण की सुविधा जन्मसिद्ध अधिकार में बदलने लगी है। हालांकि, इस मान्यता के विरोधी यह कमजोर तर्क जरूर देते हैं कि पैसे और पद भर से वो सामाजिक प्रतिष्ठा और समानता नहीं मिलती, जिसकी कि दलित और आदिवासियों को पहली दरकार है। मन से सामाजिक समता को स्वीकार करना और उसका आदर करना एक लंबी और दीर्घकालीन प्रक्रिया का हिस्सा है, जो जातिवाद की जो बुराई सैकड़ों सालों में हिंदू समाज में गहरे तक घर कर गई है, उसका उच्चाटन होने में समय लगेगा। उसके लिए कानून के साथ-साथ मानसिकता बदलने की जरूरत है। धीरे- धीरे वह बदल भी रही है। लेकिन एक जातिविहीन अथवा समतामूलक समाज काल्पनिक आदर्श स्थिति ज्यादा है। इस बात का कोई ठोस पैमाना नहीं है कि वह कौन सी स्थिति होगी जिसे सौ फीसदी समता कहा जाएगा। क्योंकि सामाजिक समता के कई कारक है और समता अपने आप में परिस्थिति, अवसर और संसाधन सापेक्ष शब्द है। दूसरे, तथाकथित ऊंची और नीची जातियों के बरक्स खुद आरक्षित जातियों के भीतर भी आंतरजातीय भेदभाव और छुआछूत कम नहीं है। इसे खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। आरक्षित जातियों में अवसरों का समान वितरण कैसे हो, इसके राजनीतिक रूप से प्रयास तो पहले से ही शुरू हो गए थे। मसलन दलितों में अति दलित अथवा महादलित, पिछड़ों में अति पिछड़ों को श्रेणियों में बांटकर उन्हें आरक्षण के लाभ देने की कोशिशें कुछ राज्यों ने पहले से शुरू कर दी थीं। लेकिन इसे सामाजिक न्याय के बजाए वोटों की गोलबंदी की पुनर्रचना के प्रयत्न के रूप में ज्यादा देखा गया। खासकर नीतीश कुमार ने बिहार में इसकी पहल तेजी की थी।

दुर्भाग्य से यह सच्चाई है कि आप किसी को कितना भी आरक्षण दें, लेकिन उसके वास्तविक लाभार्थी कुछ लोग अथवा जातियां ही होती हैं। अगर दलित या अनुसूचित जाति की ही बात करें तो देश में उनकी 16.6 फीसदी आबादी के आधार पर सरकारी नौकरियों में व शिक्षण संस्थानों में मोटे तौर पर 15 प्रतिशत और आदिवासियों को 8.6 प्रतिशत आबादी के हिसाब से 7.5 फीसदी आरक्षण दिया गया है।

अनुसूचित जाति वर्ग में यह आरक्षण कुल 1108 जातियों में बंटना होता है, लेकिन व्यवहार में वैसा होता नहीं है, क्योंकि सभी की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति व चेतना अलग-अलग है। यही कारण है कि जिन आरक्षित जातियों में अपने हितों और स्वाभिमान को लेकर ज्यादा चेतना है, वो आरक्षण का लाभ उतना ही ज्यादा उठा पाते हैं।

मोटे पर एससी श्रेणी में आरक्षण का फायदा करीब एक दर्जन जातियों ने ज्यादा उठाया है, जैसी कि जाटव, महार, मेहरा और अहिरवार आदि। लेकिन उन्हीं की एक हजार से आरक्षित बंधु जातियां इस मामले में बहुत पीछे छूट गई हैं।

अगर इस श्रेणी में सब कोटा होगा तो आरक्षण सुविधा का लाभ ज्यादा बेहतर और न्यायसंगत तरीके से वितरित हो सकता है। यही बात अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) वर्ग के लिए भी लागू होती है। वहां भी 744 जनजातियां हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ मुख्य रूप से गोंड, भील, संथाल आदि आदिवासियों ने ही उठाया है। इसका एक प्रमुख कारण शिक्षा और जागरूकता का अभाव भी है।

काफी कुछ यही स्थिति अति पिछड़ा वर्ग में भी हैं, जहां 5013 जातियां हैं, लेकिन लाभान्वित होने वाली प्रमुख जातियां यादव, कुणबी, कुर्मी, कलार, सोनी आदि ही हैं। हालांकि ओबीसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की शर्त लगा रखी है। जिसके मुताबिक वर्तमान में 8 लाख रुपए वार्षिक आय से ज्यादा वाले परिवार ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। जस्टिस रोहिणी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में ओबीसी में सब कोटा बनाने की सिफारिश की है, जिस पर सरकार अभी खामोश है।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में जिन चार जजो ने क्रीमी लेयर की शर्त को एससी/ एसटी में भी लागू करने का सुझाव दिया है, उनमें जस्टिस बी. आर. गवई भी शामिल हैं। इसके पीछे भाव यह है कि जिन लोगों को आरक्षण की वजह आर्थिक सामाजिक उत्थान हो जाए, वो आरक्षित सीट अपने दूसरे समाज व जाति बंधुओंके लिए खाली करें। खास बात यह है कि जस्टिस गवई स्वयं अनुसूचित जाति से हैं और योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण जातीय समानता के मूल भाव से दिया गया था न कि आरक्षित जातीयों में भी वर्गीकरण करने के उद्देश्य से। प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा कि अगर सब कोटा बनाना ही है तो अनारक्षित (अगड़ी) जातियों में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन वो यह भूल गए कि मोदी सरकार ने अनारक्षित जातियों के लिए आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शेष बचे 50 फीसदी में से 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। यह भी सब कोटा ही है।

यहां अनारक्षित और आरक्षित जातियों में अवसरों और प्रगति का बड़ा अंतर इसलिए दिखता है, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी में जातियों की संख्या न्यूनतम यानी 46 ही हैं, जिसमे अल्पसंख्यक आबादी (ओबीसी को छोड़कर) भी शामिल है। अनारक्षित 50 फीसदी का लाभ इन्हीं में वितरित होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आरक्षित जातियो में से कोई भी अपना वर्ग छोड़कर इन अनारक्षित जातियों में शामिल नहीं होना चाहता। जबकि यहां अवसरों का वितरण बहुत कम जातियों में होता है। उल्टे जो जातियां अभी अनारक्षित हैं, वो भी आरक्षित में जाने के लिए लड़ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा जाति।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होने में वक्त लगेगा। क्योंकि इसके लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करना होगा। हो सकता है कि सरकार अगले साल होने वाली जनगणना में इसे भी शामिल कर ले। लेकिन उसके भी पहले नई राजनीतिक गोलबंदियां तेज होंगीं। एससी/ एसटी में आरक्षण का ज्यादा लाभ उठाने वाली जातियां इस फैसले का विरोध करेंगी तो अल्प लाभ पाने वाली जातियां इसके समर्थन में जुटेंगी। यानी आरक्षित वर्गो में एक नया संघर्ष शुरू होने की संभावना है, जो सामाजिक न्याय और अवसरो की समानता की कोख से ही पैदा होगा।

सहरिया आदिवासियों को भी सुनें, स्थानीय स्तर पर आजीविका के कमजोर आधार ने बनाया मजबूर

आदिवासी कल्याण योजनाओं की बहुत चर्चा रही है और इस संदर्भ में सहरिया आदिवासियों का भी नाम आता रहा है, लेकिन झांसी जिले (उत्तर प्रदेश) के बबीना खंड में स्थित दूर-दूर की दो सहरिया बस्तियों में जाकर तो यही लगा कि यहां प्रवासी मजदूरी पर निर्भरता कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर आजीविका का आधार बहुत कमजोर है। मथुरापुर गांव की सहरिया बस्ती के लोगों ने बताया कि ज्यादातर परिवार भूमिहीन हैं व बहुत थोड़े से परिवारों के पास कृषि-भूमि है, जो बहुत कम है। सरकारी आवास योजना के अंतर्गत कुछ परिवारों के पक्के घर बन गए हैं, शेष पुराने कच्चे घरों में ही रहते हैं। जिनका हाल में पक्का घर बना है, वह भी पूरी तरह सरकारी सहायता से नहीं बन पाया। इसके लिए उन्हें कुछ कर्ज भी लेना पड़े और वह भी पांच प्रतिशत प्रतिमाह की ऊंची?ब्याज दर पर। जल के लिए सरकार ने पाइपलाइन तो बिछा दी है, पर इन नलों और पाइप में पानी अब तक नहीं आया है। अत: पहले के दो हैंडपंपों पर ही पूरी बस्ती निर्भर है। भीषण गर्मी के दिनों?में हैंडपंप जल्दी ही हांफने लगते हैं। पानी की कमी बनी रहती है और बहुत-सा समय पानी का इंतजाम करने में ही चला जाता है। मनरेगा में हाल के समय में बहुत ही कम रोजगार मिल सका है।

इन स्थितियों में ज्यादातर परिवार अपना पेट भरने के लिए प्रवासी मजदूर बनने को मजबूर हैं। महिलाओं ने बताया कि वहां जाने पर कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती हैं, पत्नी लगाकर रहना पड़ता है। धूप, वर्षा, सर्दी सभी की मार अधिक सहनी पड़ती है, पर मजबूरी है कि जाना ही पड़ता है। सेमरिया गांव की एक सहरिया बस्ती में महिलाओं ने बताया कि कभी-कभी तो प्रवासी मजदूरी में मेहनत करने पर जो मजदूरी मिलनी होती है, उसमें से कटौती कर ली जाती है। ऐसा भी हुआ है कि मजदूरी के बिना ही लौटना पड़ा। बाहर जाने पर उनकी स्थिति कमजोर होती है और कई बार उन्हें मजदूरी के मामले में ठगा जाता है। उन्होंने बताया कि आवास थोड़े से बने हैं, पर मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। गांव में बने रहें, तो गुजारा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरी करने से बच्चों की शिक्षा की क्षति तो होती है, पर फिर भी हमें जाना पड़ता है। इन महिलाओं ने बताया कि राशन तो फिर भी ठीक से मिल जाता है। पर आंगनवाड़ी से पौष्टिक आहार बहुत कम मिल पाता है। अपनी बस्ती की एक विशेष समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनके घरों के बहुत पास से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है और उनकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। इनमें बहुत करंट होता है, जो उन्हें प्रभावित करता है।

अग्निवीर का दूसरा पहलू, योजना को इस नजर से भी देखा जाए

अग्निवीर योजना के पक्ष और विपक्ष में सैकड़ों लेख लिखे गए हैं, यहां तक कि विशेषज्ञ भी भ्रमित हैं। चूंकि नकारात्मक बातें सकारात्मक बातों के मुकाबले ज्यादा फैलती हैं, कुछ राजनीतिक दल इसे गलत ढंग से पेश करते हैं, ताकि जनता को सत्ताधारी व्यवस्था के खिलाफ भड़काया जा सके। संख्या के लिहाज से हमारी सेना सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। पुरानी भर्ती प्रणाली में सेना की भर्ती शाखा भर्ती कार्यालय (बीआरओ) द्वारा की जाती थी, जहां आवेदकों का चयन कुछ खास मानदंडों के आधार पर किया जाता था। मोटे तौर पर ऊंचाई, वजन, छाती की माप के आधार पर स्क्रीनिंग होती थी। उसके बाद शारीरिक फिटनेस की जांच होती थी, जिसमें दौड़ना, पुलअप और संतुलन अभ्यास शामिल थे। छांटे गए उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता था। ज्यादातर सैनिकों (पैदल व अन्य लड़ाकू जवानों) के लिए परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती थी। चयन के बाद जवानों को संबंधित शाखा केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था और प्रशिक्षण की अवधि उसके ट्रेड की आवश्यकता के अनुसार होती थी। यहां तक कि एक ड्राइवर को भी लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। अग्निवीर योजना के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में सशस्त्र बलों से सलाह नहीं ली गई। यानी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा इस योजना को रक्षा बलों पर थोपा गया। जबकि वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला का कहना है कि सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएसी) के सेना कमांडर के रूप में उन्होंने लागू होने से पहले इस योजना पर विस्तार से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य सेना ने अपने सैनिकों को 23 सप्ताह से अधिक समय तक प्रशिक्षित नहीं किया है और अग्निवीर को छह महीने यानी 24 सप्ताह तक प्रशिक्षित किया गया है। क्या हमें प्रशिक्षण में तीन साल बर्बाद करने की जरूरत है? आप हमेशा समय सीमा को उचित विश्व मानक तक सीमित कर सकते हैं। हमें प्रशिक्षण की गुणवत्ता और कठोरता पर ध्यान देना चाहिए, न कि अवधि पर। किसी व्यक्ति के लिए पहली नौकरी की तलाश सबसे बड़ी चुनौती होती है। हर नियोक्ता अनुभव प्रमाण पत्र मांगता है। इसलिए, नौकरी चाहने वाला व्यक्ति असमंजस में फंस जाता है, क्योंकि बिना नौकरी के कार्य का अनुभव नहीं हो सकता और बिना कार्य अनुभव के नौकरी नहीं मिल सकती। अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा लाभ है 'कार्य अनुभव'। एक शानदार कार्य अनुभव और सैन्य नैतिकता से परिचय, जिसे रुपयों में नहीं मापा जा सकता। यह 'सीखते हुए कमाने' का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, इस बार के बजट में इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है। एक इंटर्न के रूप में अभ्यर्थी को प्रति महीने 5,000 रुपये मिलेंगे और काम करने का अनुभव मिलेगा। यदि कंपनी को आपका काम पसंद आता है, तो आपको वहीं नौकरी मिल सकती है या आप अपने बायोडाटा में इसका उल्लेख करके कहीं और नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप योजना रोजगार चाहने वाले स्नातकों के लिए है। अग्निवीर हर लिहाज से बेहतर योजना है। कोई भी सरकार रोजगार पैदा नहीं कर सकती। सभी राजनीतिक दलों को यह बात समझनी चाहिए और हर जगह बाधाएं खड़ी करना और अच्छी योजनाओं को भी विफल करना बंद करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बेहतर विचार है, तो उसे संसद में पेश करें। उसे सुनने के लिए सरकार तैयार है। पहले वर्ष में अग्निवीरों को 30,000 रुपये का मासिक पैकेज मिलता है, जिसमें 21,000 रुपये का इन-हैंड वेतन होता है। 9,000 रुपये अग्निवीर की तरफ से कॉर्पस फंड में जमा होता है, और इतनी ही राशि सरकार द्वारा भी इस फंड में जमा की जाती है। इस तरह से प्रभावी रूप से एक अग्निवीर का मासिक वेतन 39,000 रुपये होता है। इसके अतिरिक्त तीनों सेवाओं में लागू जोखिम व कठिनाई भत्ते और तीस दिन की वार्षिक छुट्टी, एलटीसी, कैंटीन सुविधा एवं चिकित्सा आदि की सुविधाएं मिलती हैं।

अगर अग्निवीर उद्यमी बनना चाहते हैं, तो उन्हें बैंक ऋण में प्राथमिकता मिलेगी। अगर अग्निवीर आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष प्रमाणपत्र और आगे की पढ़ाई के लिए पसंद का ब्रिजिंग कोर्स दिया जाएगा। यह मत भूलिए कि ज्यादातर अग्निवीर मात्र 12वीं पास हैं, वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं। अग्निवीर को उनकी नियुक्ति अवधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। समय के साथ अग्निवीरों का वेतन बढ़ता जाता है और चौथे साल का पैकेज 40,000 रुपये प्रति माह होता है। चार साल की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीर को सेना में रखा जाता है, बाकी को अपने घर भेज दिया जाता है, जो दुनिया से जूझने के लिए पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उन्हें एकमुश्त 12 लाख रुपये की कर-मुक्त राशि भी मिलती है। सरकार के लिए लागत (सीटीजी) कंपनी के लिए लागत (सीटीसी) के समान ही है। मुफ्त बोर्डिंग, लॉजिंग, (राशन), यूनिफॉर्म और अन्य चीजों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसे मापना कठिन है, लेकिन बचत के मामले में यह बड़ा सहारा होगा। सेना का प्रशिक्षण काफी खर्चीला होता है और अग्निवीर को यह मुफ्त मिलता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर साल?देश में 95 लाख युवा स्नातक बनते हैं और उनमें से ज्यादातर बेरोजगार रहते हैं। एक औसत स्नातक को हर महीने दस से पंद्रह हजार रुपये से ज्यादा नहीं मिलते। कोई भत्ता भी नहीं मिलता। चार साल स्नातक करने और चार साल काम करने के बाद भी एक सामान्य व्यक्ति अग्निवीर के बराबर रोजगार पाने की स्थिति में नहीं होता है। अग्निवीर चार साल सेना में काम करने के बाद दूसरी नौकरी पा सकता है और रोजगार करने के समानांतर पढ़ाई भी कर सकता है। अग्निवीर प्रशिक्षित, अनुशासित और कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति बन जाता है। अग्निवीरों को 42 महीने का कार्य अनुभव मिलता है, जो सामान्य स्नातक की तुलना में रोजगार पाने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। सेना में उसे नेतृत्व, टीमवर्क और एक विशिष्ट संगठन से जुड़े होने की भावना मिलती है। आज कंपनियां अच्छे अनुशासित कार्यबल की तलाश कर रही हैं।

शराब परिवहन परमिट की शर्तो के उलंघन का मामला

दोषियों को एक वर्ष का कारावास एवं पचास हजार रुपया जुर्माना

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी सिटी दमोह, अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत चल रहे बारह वर्ष पुराने मामले में निर्णय करते हुए दो आरोपियों को अवैध तरीके से शराब परिवहन के मामले में कारावास सहित जुर्माना एवं वाहन मालिक आरोपी को जुर्माना से दोषी मानते हुए दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर द्वारा की गई। अभियोजन अनुसार मामला इस प्रकार है, दिनांक 9 जून 2012 को थाना नोहटा में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तलागांव के पास एक बोलेरो गाड़ी में शराब लेकर विक्रय हेतु वहां स्थित गांव में कुछ व्यक्ति ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना नोहटा पुलिस ग्राम तलागांव पहुंची और वहां पर एक बोलेरो गाड़ी को जिसमें आरोपी देवी सिंह पिता रतन सिंह निवासी बालाकोट, रसीद खान उर्फ कुद्दू पिता कुन्नू खान निवासी सीताबावली बैठे हुए थे को घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 14 पेटी कार्टून में शराब मिली पुलिस ने शराब रखे होने के संबंध में उनसे कागजात मांगे तो उन्होंने उस समय कागज नहीं होना बताया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। दूसरे दिन पुलिस को शराब परिवहन के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया था कि शराब को अभाना शराब दुकान से हृदयपुर शराब दुकान परमिट प्राप्त कर ले जा रहा है, परंतु पुलिस ने परमिट में लिखे मार्ग, जो अभाना शराब दुकान से हृदयपुर शराब दुकान ले जाने का था उससे अलग मार्ग पर यह बोलेरो गाड़ी शराब ले जाते पकड़ी थी पुलिस ने परमिट को ही संदिग्ध एवं कूटरचित माना, यह भी माना कि शराब पकड़े जाने के बाद अधिकारियों से मिलकर यह परमिट झूठा बनाया गया है, पुलिस अपनी विवेचना में इस बात पर पहुंची कि अभाना शराब दुकान और हृदयपुर शराब दुकान के लाइसेंसी गांव-गांव में जाकर शराब को अवैध रूप से विक्रय करते हैं पुलिस ने दोनों शराब दुकानों के लायसेंसीओ सहित मैनेजर संजय पिता शिवकुमार यादव निवासी आमचोपरा, कमलेश पिता श्यामले पटेल निवासी दमोह और वाहन मालिक शैलेश शर्मा पिता सुभाष शर्मा निवासी अभाना को भी आरोपी बनाकर मामला न्यायालय में पेश किया। मामला न्यायालय के समक्ष आने पर आरोपियों की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वह लोग अभाना शराब दुकान से परमिट प्राप्त कर शराब को हृदयपुर दुकान में ले जा रहे थे, वह अपने परमिट के निर्धारित मार्ग पर ही जा रहे थे परंतु कुछ लोगों ने उन्हें डरा धमका कर उनका रास्ता बदल दिया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात आरोपी देवी सिंह एवं रशीद खान को एक एक वर्ष के साश्रम कारावास और पचास हजार रुपए के जुर्माना और वाहन मालिक शैलेश शर्मा को निजी रूप में पंजीकृत वाहन का व्यवसायिक उपयोग करने का दोषी मानते हुए तीन हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कर निर्णय में लिखा कि प्रस्तुत परमिट उचित अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, परंतु परमिट में दी गई शराब की मात्रा से अधिक शराब गाड़ी में पकड़ी गई है और परमिट में बताए गए मार्ग से हटकर अन्य मार्ग पर शराब पकड़ी गई है, ऐसे में शराब ले जाने वाले आरोपी को दोषी माना जाना ही उचित होगा, परंतु शराब दुकान के मैनेजर एवं लाइसेंसियो को दोषमुक्त करते हुए माना कि इन्हें दोषी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि लाइसेंसी अपने सेवकों के उन्ही कार्यों के लिए दायित्ववान होंगे जो मदिरा दुकान में उसके द्वारा किए गए हो या प्रदत्त लाइसेंस या परमिट के अनुसरण में किए गए हो ना कि सेवक के अन्य किसी प्रकार के कार्य के लिए।

ट्रक ने कार को मारी टक्कर, पांच की मौत

सभी मृतक एक ही परिवार के जेसीबी सब्बल से कार के गेट तोड़कर निकालने पड़े शव

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह! सागर में ट्रक और कार की आमने-सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर है। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक कार के ऊपर चढ़ गया। इसे जेसीबी की मदद से हटाकर सब्बल की मदद से कार के गेट तोड़े गए। तब लोगों को निकाला जा सका। हादसा शुक्रवार शाम करीब साढ़े 6 बजे सानौधा थाना इलाके में सागर-गढ़ाकोटा रोड पर हुआ। थाना प्रभारी गौरव गुप्ता ने बताया कि कार में 6 लोग सवार थे। परिवार सागर में निजी काम पूरा कर अपने घर परसोरिया लौट रहा था। इसी दौरान जटाशंकर घाटी के पास दमोह की ओर से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी राजस्थान पासिंग ट्रक का ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है **हादसे में इनकी गई जान**- एक्सीडेंट में सागर के परसोरिया निवासी समाजसेवी सुरेश जैन के परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में उनकी पत्नी प्रभा जैन (60), मझला बेटा संदेश जैन (38), संदेश की पत्नी निधि (32), छोटी बहू नैंसी पति शैलेंद्र जैन (30) और नाती उत्कर्ष पिता शैलेंद्र जैन (6) शामिल हैं। कार चला रहे ड्राइवर बबलू पिता अजीत खान (40) को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर है बहू के बीमार पिता को देखने गए थे पुलिस के मुताबिक, जैन परिवार की छोटी बहू नैंसी जैन के बीमार पिता सागर में निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हीं को देखने के लिए सभी लोग सागर गए थे। घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए सूचना मिलते ही नरयावली विधायक प्रदीप लारिया भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एसपी से बात कर पूरा मामला जाना। घायल ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाने में मदद भी की।

बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने शासकीय शिक्षण संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया

निरीक्षण दौरान विधायक ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश व बच्चों के साथ किये भोजन

लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ लालबर्रा, बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे 1 अगस्त को औचक निरीक्षण करने शासकीय विघालय पहुची तथा विघालय कि व्यवस्था देखी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए ।जिसमे शासकीय हाई सेकेंड्री स्कूल बिरसोला के छात्र छात्राओं से वार्तालाप किया गया एवं उनकी समस्याओं को सुना गया साथ ही मध्यान भोजन किचन रूम का भी निरीक्षण किया गया जहाँ पर तैयार मध्यान भोजन की गुणवत्ता भी देखी गई, इसी क्रम में ग्राम निलजी के उच्च माध्यमिक शाला व माध्यमिक शाला का भी विस्तृत निरीक्षण किया गया तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक गणों के साथ मध्यान भोजन भी किया गया एवं विद्यालय की भवन संबंधी समस्याओं को भी देखा गया तत्पश्चात् पौधा रोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में एक और कदम बढ़ाया गया । इसके पश्चात ग्राम बल्लारपुर के एक शाला एक परिसर विद्यालय का निरीक्षण किया गया जहां पर छात्र छात्राओं एवं शिक्षक गणों से विद्यालय के विषय में चर्चा हुई जहां पर हमे अत्यंत अनियमितता देखने को मिली तथा शाला भवन की जर्जर स्थिति भी देखने को मिली । विधायक महोदया द्वारा शिक्षण के विषय को गंभीरता एवं प्राथमिकता से लिया गया है, क्योंकि छात्र छात्राओं को यदि यथोचित सुविधा मिलेगी तो वो और अच्छे से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का और अपना नाम रौशन करेंगे ! विधायक महोदया ने कहा कि वह निरीक्षण के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में व्याप्त समस्याओं को समझकर उसे दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि देश के भविष्य छात्र हमारे देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके।

जनसंपर्क अमले की मानवता व सहृदयता के बाद भी घायल कबूतर को नहीं बचाया जा सका

उपचार के दौरान पशु चिकित्सालय में घायल कबूतर ने तोड़ा दम

सुनील यादव । सिटी चीफ कटनी, माधवनगर स्थित सर्किट हाउस के सड़क में चोटिल होकर फड़फड़ा रहे कबूतर का रेस्क्यू कर जिला जनसंपर्क अधिकारी मनोज श्रीवास्तव और फोटोग्राफर लाल जी शर्मा घायल कबूतर को झिंझरी स्थित पशु चिकित्सालय उपचार हेतु लेकर पहुंचे। जहां उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी ने घायल कबूतर का गहन परीक्षण किया और बताया कि बाज आदि किसी शिकारी जानवर द्वारा इसकी गर्दन में प्राणघातक हमला किये जाने से कबूतर का स्पाइनल कार्ड टूट गया है। इसलिए इसकी गर्दन लटक गई है। पशु चिकित्सक द्वारा कबूतर की जिंदगी बचानें के अथक प्रयासों के बाद भी उपचार के दौरान ही पशु चिकित्सालय झिंझरी मे कबूतर ने दम तोड़ दिया। मृत कबूतर का मथुरा प्रसाद नामदेव ने विधिवत फूल अर्पित कर भू- समाधि दी। विदित हो कि राजस्व महाअभियान की समीक्षा के लिए कटनी पहुंचे संभागायुक्त अभय वर्मा के सर्किट हाउस मे अल्प विश्राम के दौरान जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी सर्किट हाउस में ही मौजूद रहे। संभागायुक्त के जबलपुर प्रस्थान करने के बाद जब सभी अधिकारी लौट रहे थे तभी यह घायल कबूतर जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री श्रीवास्तव को सर्किट हाउस के सामनें सड़क पर घायल अवस्था में फड़फड़ाता हुआ दिखा था।

स्थगन के आदेश की अवहेलना कर अवैध निर्माण कार्य जारी

अमरपुर पुलिस चौकी में सूचना देने पर भी नही रुका निर्माण कार्य

शासन – प्रशासन मौन जिम्मेवार कौन?

श्रीनिवास मिश्रा । सिटी चीफ मध्य प्रदेश – संपूर्ण मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा लोगों के जमीन संबंधी किसी भी प्रकार के बाद विवाद के निदान को लेकर संपूर्ण प्रदेश में स्थानीय प्रशासन को एक विशेष महिम के साथ विवादित मामले को सुलझाने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है लेकिन मध्य प्रदेश में ही शासन प्रशासन की जानकारी के बावजूद भी दबंगों द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर अवैध निर्माण कार्य जारी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला मध्य प्रदेश के उमरिया जिला अन्तर्गत तहसील न्यायालय मानपुर नायब तहसीलदार के द्वारा दिनांक 12/07/24 को जारी स्थगन आदेश मे आवेदक नारेंद्र सिंह पिता हरीश सिंह बनाम सूर्यबली पिता विश्वनाथ सिंह निवासी ग्राम देवगंवा थाना इंदवार के अवैध निर्माण कार्य के मामले को लेकर स्थगन आदेश जारी किया गया की विवादित जमीन में किसी भी पक्ष द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। उपयुक्त कार्रवाई के लिए आदेशित आदेश में दिनांक 26.7.2024 को दोनों पक्षों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा जबकि आवेदक एवं अनावेदक दोनों के समक्ष तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार से निर्माण कार्य नहीं किए जाने की बात कहकर अगली पेशी का दिन तय कर दोनों को आदेशित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए विवादित जमीन में निर्माण कार्य जारी कर लिया गया है। जिसकी सूचना नजदीकी पुलिस चौकी अमरपुर में देने के बाद भी किसी प्रकार से वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दबंगों का अवैध निर्माण कार्य करवाने में स्थानीय शासन प्रशासन का खुला संरक्षण प्राप्त है। जिसकी जानकारी आवेदक ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार एवम शासन प्रशासन को अवगत कराकर दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेला किए जाने पर दंडनात्मक कार्यवाही कर न्याय दिलाने की उचित कार्रवाही सुनिश्चित करें।

तालाब में दुबे युवक को ग्रामीणों ने समझा मृतक

कटनी पुलिस की तत्परता से सीपीआर से बची युवक की जान

सुनील यादव । सिटी चीफ कटनी, कुएं में डूबे युवक को ग्रामीणों ने मृतक समझ कटनी के ढीमरखड़ा पुलिस को सूचना दी लेकिन सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस देवदूत बनकर पहुंची और युवक को कुएं से बाहर निकलवा पुलिस वाहन में ही युवक को लगातार धक्का देकर उनकी सांसे वापस लाई और उसे तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची कहा उसका इलाज जारी है वही इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। कटनी जिले के एएसपी संतोष डहरिया ने बताया की कटनी जिले के ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के झिन्ना पिपरिया के तालाब में सोनू पटेल नमक एक युवक की डूबने की सूचना पर ढीमरखेड़ा पुलिस को तत्काल सूचना पाते ही थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा गया और वही ग्रामीणों की मदद से सोनू पटेल को तालाब से निकाल गया जिसे सभी लोग मृत समझ रहे थे ...तभी युवक के शरीर में हल्की सी हलचल सी महसूस हुई तो फौरन ढीमरखेड़ा पुलिस के स्टाफ ने सीपीआर देना शुरू कर दिया काफी देर तक सीपीआर देने के बाद युवक की सास वापस आ गई उसके बाद फौरन ही युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहा उसकी हालत अब अच्छी है।

कटनी में 35 फीट ऊंचे पुल से उफनती नदी में कूदते बच्चो का वीडियो वायरल

कटनी एसडीएम नगर निगम और कोतवाली पुलिस को दिए जाँच के निर्देश

सुनील यादव । सिटी चीफ कटनी, कटनी जिले में रुक रुक हो रही बारिश से नदिया उफान पर है और इस उफनती नदी में 20-20 फीट ऊंचे पुल से बच्चे की जान की बाजी लगाकर छलांग लगा रहे है जिसका एक विडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा जिसमे कई बच्चे एक के बाद एक नदी में कूदते दिखाई दे रहे है। वायरल वीडियो कटनी जिले के गाटर घाट स्थित रेलवे ब्रिज का बताया जा है जहां स्थानीय क्षेत्र के करीब आधा दर्जन बच्चे नहाने के लिए पहुंचे थे लेकिन उनके नहाने के इस तरीके को देख हर कोई दंग है क्योंकि यह तमाम बच्चे कटनी दमोह रेल मार्ग में बने ब्रिज पर चढ़ गए और बिना डर के एक के बाद एक छलांग लगाने लगे आपको बता दे ब्रिज करीब 35 फीट ऊंचा हैं लेकिन पानी के उफान के चलते उसकी गहराई 15 फीट गहरी हो गई है और यहां बच्चे बिना जान की परवाह किए ही उसमे कूदते दिखाई पड़ रहे है वही जब पूरे मामले की जानकारी कटनी एसडीएम प्रदीप मिश्रा को लगी तो उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कहते हुए नगर निगम कटनी और कोतवाली पुलिस को उचित दिशा निर्देश देने की बात भी कही है।

करीब 12 लाख से ज्यादा कांवड़िए निकले सहारनपुर से

लाखों शिवभक्तों ने आज शिवरात्रि पर विधिपूर्वक शुभमुर्हूत में जलाभिषेक किया

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

देवबंद। सहारनपुर, आज श्रावण मास की शिवरात्रि के अवसर पर जनपद में लाखों शिवभक्तों ने विधिपूर्वक शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और पंचामृत से स्नान और रूद्राभिषेक किया। सहारनपुर महानगर में भूतेश्वर महादेव, बागेश्वर महादेव, पाठेश्वर महादेव, पातालेश्वर महादेव और गांव बरसी में स्थित महाभारतकालीन बरसी महादेव, सरसावा में बनखंड़ी महादेव, नकुड़ में नकुलेश्वर महादेव, गंगोह में गुड़छप्पर महादेव और देवबंद में मनकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा को चंदन, पुष्प, बेलपत्र, धूप आदि किया। साथ ही भोगादि करके पंचामृत के साथ जलाभिषेक किया। पूरे जनपद में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच 12 जुलाई से आरंभ हुई कांवड़ यात्रा आज धूमधाम एवं भक्तिभाव के साथ संपन्न हो गई। कांवड़ियों यात्रियों पर जिलाधिकारी मनीष बंसल और एसएसपी मोहित सजवान

द्वारा हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी। आज डाक कांवड़ियों की संख्या ज्यादा थी। अनेक कांवड़िए इस बार 501 लीटर गंगाजल की कांवड़ भी लेकर आए।

सहारनपुर :- में 09 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन की 100 वीं वर्षगांठ के शुभारंभ अवसर पर होंगे भव्य कार्यक्रम

तिरंगे रंग के 100 गुब्बारे उडाकर होगा आयोजन का शुभारम्भ

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100 वीं वर्षगांठ की तैयारियों के संबंध में बैठक आहूत की गयी।जिलाधिकारी ने बताया कि 09 अगस्त को साइकिल सवार स्वयं सेवकों, विद्यार्थियों द्वारा शहीद स्मृति यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सभी स्वयं सेवकों, विद्यार्थियों की साइकिलों पर क्रांतिकारियों द्वारा दिये गये लोकप्रिय नारों की कार्ड बोर्ड की पट्टिकाएं रहेंगी एवं सभी वॉलिन्टियर्स तिरंगा के रंगों की टी-शर्ट में रहेंगे। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि तिरंगे रंग के 100 गुब्बारें उडाकर आयोजन का शुभारम्भ किया जाएगा। पुलिस बैण्ड द्वारा राष्ट्रधुन का वादन किया जाएगा एवं काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित अभिलेख एवं चित्र प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथिगणों के द्वारा स्वंतत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा।

इसी के साथ राष्ट्रभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि संबंधित सभी विभाग सौंपी गयी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझकर समय से सभी तैयारी पूर्ण करना सुनिश्चित करें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन एक महत्वपूर्ण घटना है। इस ऐतिहासिक घटना को 09 अगस्त, 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी में क्रांतिकारियों द्वारा चलाये जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को धन की आवश्यकता के लिए क्रियान्वित किया गया था। इस घटना से क्षुब्ध अंग्रेजी सत्ता ने हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व यात्रियों की हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिसमें शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्ला खां और शहीद रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गयी। 6 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम चार वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम कालापानी, आजीवन कारावास तक का दण्ड दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, समस्त एसडीएम सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उप निबन्धक कार्यालय का किया निरीक्षण

दस्तावेजों को प्रतिदिन किया जाए अपलोड :- जिलाधिकारी मनीष बंसल

गौरव सिंघल । सिटी चीफ

सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा कार्यालय उप निबन्धक सदर प्रथम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा पत्रावलियों के व्यवस्थित रख-रखाव के सख्त निर्देश दिए गये। दस्तावेजों के प्रतिदिन अपलोड न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि दस्तावेजों के प्रतिदिन अपडेशन में कोई लापरवाही न बरती जाए। जिन विक्रय पत्रों की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है वह कार्यालय में लम्बित न रहें। डीएम मनीष बंसल ने कार्यालय में लगे

सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में बेहतर साफ-सफाई के साथ ही फाइलों का ठीक प्रकार से रख-रखाव के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कोई भी प्राइवेट व्यक्ति कार्य करता हुआ नहीं पाया गया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुर्तीजापुर येथे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती दिनी रक्तदान करून वाहिली आदरांजली

डॉ संजय चव्हाण । सिटी चीफ

अकोला, नेहरू युवा केंद्र अकोला क्रीडा व युवक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा बहु . क्रिंडा व सांस्कृतिक मंडळ कोकणवाडी मुर्तिजापुर, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे जयंती उत्सव समिती मूर्तिजापूर व श्री आईबाबा बंहू संस्था सालतवाडा. यांच्या संयुक्त विद्यमाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 104 व्या जयंती निमित्त रक्तदान शिबिराचे स्थानिक भक्तीधाम मंदिर समता नगर येथे आयोजन करण्यात आले होते .सदर रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन आमदार हरीष भाऊ पिंपळे व मान्यवरांच्या हस्ते लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून रीतसर शिबिरास सुरुवात करण्यात आली, कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक विलास वानखडे यांनी केले . सर्वप्रथम महिला वर्गातील ओम शांती ओम ब्रह्मकुमारीजच्या मुक्ता दीदी व

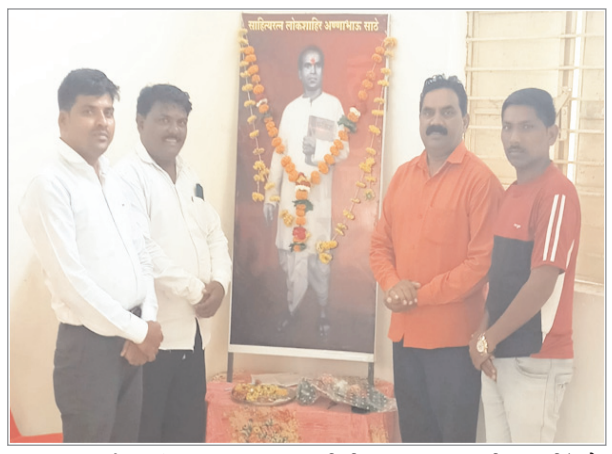

अंकिता खंडारे यांनी प्रथम रक्तदान करून खरी आदरांजली अर्पण केली. 41 वेळा रक्तदान करते समाजसेवक द्वारकाभैय्या दुबे, पोलीस कर्मचारी मंगेश विल्हेकर, अरूण थोरात , होमगार्ड सैनिकांचा प्राण वाचवणारे जिगरबाज होमगार्ड सैनिक अक्षय ठाकरे, संदीप सोनवणे, राजेंद्र कुकलवार , यांच्यासह आदी सर्वांनी रक्तदान करून आपले कर्तव्य निभावले. या शिबिरास आमदार हरिभाऊ पिंपळे, कमलाकर भाऊ गावंडे, कैलास भाऊ महाजन, द्वारका भैया दुबे, सत्यनारायण तिवारी, इब्राहिम भाई घानीवाले, रवि राठी, अशोक थोरात, परिमल कांबळे, सुनील पवार, अरविंद तायडे, सुनील भोजगडीया, पत्रकार प्रवीण ढगे, मधुकरराव इंगोले, महादेव इंगोले, सुधाकरजी गौरखेडे, उमाळे काका , सो .मीना जवादे , शेख रफिक भाई, पत्रकार व गझलकार मिलिंद इंगळे, महादेव पाटील यांनी ही रक्तदान करून आपले कर्तव्य बजावले. कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, सामाजिक, पत्रकार, राजकीय, पोलीस कर्मचारी, होमगार्ड सैनिकांसह ,सर्वांनी भेटी देऊन रक्तदान केले, सदर कार्यक्रमास सर्व समाजातील महिला व पुरुषांनी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित दर्शविली. दीपक खंडारे, वैभव वानखडे, दिनेश श्रीवास, रवी माडकर, निलेश वानखडे, अवधूत थोरात, दिगंबर सरदार, विलास सावळे, आकाश वानखडे, रणजीत शिरसाठ, सह सर्वांनी परिश्रम घेतले. लेडी हार्डिंग रक्त संकलन चम्मूचे सहकार्य लाभले. कार्यक्रमाचे संचालन नेहरू युवा बहुउद्देशीय क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ कोकणवाडी अध्यक्ष विलास वानखडे यांनी केले. तर आभार श्री आई बाबा बहुदेशीय संस्थेचे गजानन चव्हाण यांनी मानले.

महान येथील काटेपूर्णा धरणाचे काटेपूर्णा नदीपात्रात पाणी सोडणे बाबत जाहीर सुचना

डॉ संजय चव्हाण । सिटी चीफ

अकोला, आज दि. 1/08/2024 रोजी काटेपूर्णा प्रकल्पाची पाणी पातळी अंदाजे 80% पाणीसाठा झाला असण्याची शक्यता आहे. काटेपूर्णा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये पाऊस सुरू असून धरणाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने येणाऱ्या 24 तासात कधीही काटेपूर्णा प्रकल्पाचे द्वार उघडून पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात सोडण्यात येऊ शकते. येणाऱ्या येव्या नुसार वक्रद्वार उघडून पुराचे पाणी नदीपात्रामध्ये सोडण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.तरी नदी काठच्या गावांतील नागरिकांनी सावध राहावे तसेच नदी पात्र ओलांडू नये. नदीकाठावरील गावांना

आपल्या स्तरावरून सतर्क करण्यात यावे. काटेपूर्णा प्रकल्प आज दिनांक 01/08/24 रात्री अकरा वाजता काटेपूर्णा प्रकल्पाचे वक्रद्वार क्रमांक 1,5,6,10, प्रत्येकी 30 CM उघडून काटेपूर्णा नदीपात्रात 92.23 घनमीटर / सेकंड (3257 क्यू शेख) पाणी सोडण्यात आले आहे कधी नदी काठावरील नागरिकांनी सतर्क राहावे।

राहुल गांधी वरील टीकेला अमरावती काँग्रेसकडून प्रतिउत्तर

जिल्हाधिकारी का दादा समोर निषेध आंदोलन, अनुराग ठाकूर यांना टोला

डॉ संजय चव्हाण । सिटी चीफ

अमरावती, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी लोकसभेत जात नाही आहे जनगणनेचा मुद्दा मांडला नाही भाजपचे मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी खासदार राहुल गांधीची जात विचारून त्यांचा अपमान केला. त्यांच्या निषेध म्हणून अमरावतीशहर काँग्रेसने आज भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात स्त्री व नारे जाणारे बाजी करीत जिल्हा कचोरीवर धरणे दिले शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी पालकमंत्री डॉ सुनील देशमुख, माजी महापौर तथा काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते मिलिंद चिमटे, अन्या प्रवक्तेभ्यऑड. दिलीप ऐडतकर, प्रदेश उपाध्यक्ष भैय्या पवार, प्रदेश सचिव असिफ तवव्काल, महिला काँग्रेस अध्यक्ष जयश्री ताई वानखडे आदींनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. सर्व समाज घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय व हक्क मिळावेत यासाठी, जातनिहाय जनगनना करणे गरजेचे आहे. काँग्रेस पक्ष व इंडिया आघाड्यातील इतर मित्र पक्ष यासाठी कटिबद्ध आहेत. परंतु भारतीय जनता पक्षाचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध आहे. त्यातूनच हा लांचनास्पद प्रसंग घडला असून आम्ही त्याचा त्रिव निषेध करतो.

अशा प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या. दरम्यान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कविता वार अनुराग ठाकूरच्या विधानाचे कौतुक केले, ते याहून गंभीर आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेले व्यक्ती जात, धर्माच्या नावावर तेढ निर्माण करणाऱ्या विधानाचे समर्थन करतो, हे या देशाचे दुर्दैव आहे. दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाने कितीही विरोध केला, शिव्या दिल्या, अडथळा आणला तरीही जातनीहाय जनगणना होणारच, असेही यावेळी ठासुन सांगण्यात आले. संजय वाघ, विनोद मोदी, अशोक डोंगरे, हाजी नजीर खान बीके, भैय्यासाहेब नीचळ,प्रा. अनिल देशमुख, वंदना थोरात, शिल्पा राऊत, योगिता गिरासे, अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. खासदार राहुल गांधी यांची जात विचारण्यासारख्या लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेक नाकारला होता त्यांनी आगरकर, मा. ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, प्रबोधनकार ठाकरे, विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या थोर महापुरुषांच्या कार्यात विघ्न आणले. अशी मांडणीही यावेळी करण्यात आली.

काटेपूर्णा प्रकल्प पूर नियंत्रण कक्ष

सरकार म्हणतात झाडे लावा व झाडे जगवा कसाबला गाय ढोरं विकु नका आणि दुसरीकडे जंगल नष्ट करण्याचं काम चालू आहे

डॉ संजय चव्हाण । सिटी चीफ

अकोला, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी कीमान 40 ते 50 एकर जमीन लागत आहे आणि हि ई क्लास जमीन म्हणजे गाय ढोराचे चारूयाचे ठिकाण आणि झाडे लावाची जमीन. हा सौरऊर्जा प्रकल्प शेतकऱ्यांना कमी दरात दिवसा विज मिळण्याकरिता आहे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे परंतू सरकाराला खरोखर शेतकऱ्यांचं हिताचा विचार करायचा आहे तर बरेच ठिकाणी पडीत बंजर शेती आहेत ती भाड्याने सरकारने घ्यावी त्या पडीत असलेल्या शेती च शेतकऱ्यांना मोबदला मिळेल आणि कोणत्याही प्रकारचे झाडे तुटणार नाही व गाई ढोरांना चारा सुद्धा मिळेल आणि कसाबाला ढोरं ईकल्या जाणार नाही नाही.आपण हिंदू लोक गाय ला आई मानतो गौ माता हि सुरक्षित राहिली पाहिजे आणि तेवढेच महत्त्वाचं झाडे जगवणे पण खूप अति आवश्यक

आहे येणाऱ्या काळात गरज नसतील तेवढी टेक्नॉलॉजी चा वापर होईल अनेक प्रकल्प उभारता येईल परंतु त्या काळात प्रत्येक जीवासाठी अत्यंत आवश्यक असणारा एक झाड सुद्धा लावून वाढवता येणार नाही त्या अनुषंगाने सरकाराने काळजीपूर्वक विचार करायला पाहिजे. अशी मागणी अखिल भारतीय बंजारा क्रांती दलाचे. (प्रदेश सरचिटणीस तथा मा.उपसरपंच) दिनेश राठोड

सहारा पीड़ितो को न्याय दिलाने कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी फिर उतरे मैदान में

अमित शाह के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग की

राघवेन्द्र सिंह डोडीया । सिटी चीफ । जावरा। जनआंदोलन न्याय मोर्चा के माध्यम से देश के करोड़ों सहारा पीड़ितों की राशि लोटाने की मांग को लेकर दिल्ली और लखनऊ तक लंबे समय से जारी संघर्ष अल्प विराम के बाद पुनः जीवित हो गया हैं। सहारा पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी के इस मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित 16 अन्य पर दर्ज किए प्रकरणों के बाद अब इस मामले में देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को भी धारा 406, 420 के तहत आरोपी बनाए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में सहारा पीड़ित मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विरेन्द्रसिंह सोलंकी और निजाम काजी के नेतृत्व में शहर थाने पर पहुंचे और प्रकरण करने का आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं मामले में आगामी 6 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर न्याय मोर्चा द्वारा जंगी प्रदर्शन किए जाने और उसमें अधिक से अधिक की संख्या में सहारा पीड़ितों के शामिल होने का अनुरोध भी किया हैं। शुक्रवार को दोपहर करीब साढ़े 11 बजे सहारा पीड़ित शहर थाने पर पहुंचे और केन्द्रीय मंत्री अमित शाह को इस मामले अरोपी बनाने की मांग को लेकर थाना प्रभारी जितेन्द्रपालसिंह जादौन को आवेदन पत्र सौंपा। पत्र में पीड़ितों ने बताया कि गत 03 जनवरी 22 को जावरा निवासी दिलीप राव तथा अन्य की रिपोर्ट पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय, सपना राय सहित कंपनी के 16 डायरेक्टरों पर धारा 406, 420 भा.द.स. तथा म.प्र. में निष्क्षेपको के हिंतो का संरक्षण अधिनियम 2000 के धारा 6 (1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें अब तक मात्र दो आरोपी देवेन्द्र शर्मा तथा करूणेश अवस्थी की गिरफ्तारी हुई है, उक्त एफ.आई.आर. के पश्चात् सहारा पीड़ितो की राशि के भुगतान की कार्यवाही चल ही रही थी। इसी दौरान दिनांक 29 मार्च 2023 को केन्द्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने पुरे देश के समक्ष टेलीविजन चेनलों तथा समाचार पत्रो को बयान दिया कि हमने सभी सहारा पीड़ितों की राशि वापिस करने की निर्णय किया है, अगले 9 माह में सहारा इण्डिया कंपनी की ठगी से पीडित 10 करोड़ से अधिक निवेशकों की एक-एक पाई वापिस करेंगे जिसके प्रथम चरण में प्रत्येक पीड़ित को 10 हजार रूपये तक की राशि अगले चार माह में उनके खातो में लोटाई जाएगी।

घोषणा के बाद बना सहारा सेबी रिफण्ड पोर्टल - केन्द्रीय मंत्री अमित शाह की घोषणा के बाद तत्काल देशभर के सहारा पीड़ितों की राशि लोटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहारा सेबी रिफण्ड पोर्टल बनाकर पीड़ितों को भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई हैं। वहीं समस्त राज्य सरकारों को भी सहारा प्रबंधन के विरूद्ध प्रारंभ की गई सभी कानूनी प्रक्रियाओं को रोकने के निर्देश जारी कर दिए, जिसके बाद कार्रवाई पर विराम लग गया। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने रीट याचिका

क्रमांक 191/2022 (पिनाक पाणी मोहंती बनाम भारत संघ और अन्य) में दिनांक 29 मार्च 23 को यह आदेश दिया था कि सेबी के पास सहारा की कुल जमा नगद राशि 24,979.67 करोड़ में से प्रथमतः 5 हजार करोड़ की राशि सेन्ट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी नईदिल्ली को जारी किया जावे, तथा जब यह राशि पीड़ितो की बंट जावे तो शेष राषि तत्काल जारी की जावे।

झुठे निकले केन्द्रीय मंत्री के दावे - केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा अनुसार सहारा समूह की चार बुहराज्यीय सहकारिता समितियों अर्थात् सहारा क्रेडिट कोपरेटिव सोसायटी, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसायटी, हमारा इण्डिया क्रेडिट कोपरेटिव सोसायटी तथा स्टार मल्टीपर्पस सोसायटी के जमाकर्ताओं को उनकी वैध धनराशि के रिफण्ड के दावे की प्रस्तुति के 18 जुलाई 23 को सी.आर.सी.एस. द्वारा सहारा रिफण्ड पोर्टल बनाया गया तथा मंत्री के दावे अनुसार प्रत्येक आवेदक को शुरू के चार माह में प्रथम किश्त के रूप में 10 हजार तथा शेष सम्पूर्ण राशि 9 माह में अदा की जाना थी, तथा सहारा की शेष कंपनियों की राशि की अदायगी 4 कॉपरेटिव सोसायटियों की राशि निवेशको को मिलने के उपरांत दिये जाने का दावा किया गया। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के इस झुठे दावे तथा प्रलोभन के बाद सहारा समूह के विरूद्ध गत 15 माह से सभी तरह की कानूनी कार्यवाहियां रोक दी गई परन्तु करीब 15 माह बीत जाने के बाद भी सहारा पीड़ित दर-दर की ठोकरे खा रहें है, तथा उन्हें सम्पूर्ण राशि तो ठीक प्रथम किश्त की 10 हजार रूपये की राशियां भी प्राप्त नहीं हुई और इस तरह केन्द्रीय के दावे झुठे साबित हुए।

महज 341 करोड़ की धनराशि का ही भुगतान हो पाया - सी.आर.सी.एस. दिल्ली द्वारा सूचना के अधिकार के तहत 08 जुलाई 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार जून 2024 तक देशभर के लगभग 1 करोड़ 24 लाख जमाकर्ताओं ने 85 हजार 806 करोड़ रूपये की धनराशि के लिए पोर्टल पर क्लेम किए, जिसमें से मात्र 3 लाख 91 हजार 767 जमाकर्ताओं को 341 करोड़ रूपये की धनराशि का भुगतान हुआ है। जावरा क्षेत्र के हजारो निवेशकों में से कुछ नाममात्र के लोगो का ही भुगतान रिफण्ड पोर्टल बनने के बाद हो पाया है, तथा शेष सभी आवेदनों को जानबुझकर देशभर की तरह अनावश्यक कमियां निकालकर रिजेक्ट किया जा रहा है। सहारा समूह द्वारा भी अब तक सी.आर.सी.एस. को 2.86 करोड़ जमाकर्ताओं का ही डाटा उपलब्ध करवाया गया है।

धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से बनवाई गई ऐसी पॉलिसी - आवेदन में बताया कि केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने जान बुझकर देश के करोड़ो सहारा निवेशको से धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से तथा हिन्दुस्तान के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले के अपराधियों को बचाने के लिए आरोपियों से मिलीभगत कर ऐसी पॉलिसी बनवाई ताकि वर्षों तक सहारा पीड़ितो को उनके हक की राशि का भुगतान न हो तथा आरोपियों को कानूनी सरंक्षण भी मिलता रहे।

इनकी रही उपस्थिति - शहर थाना प्रभारी जितेन्द्रपालसिंह जादौन को केन्द्रीय मंत्री को आरोपी बनाए जाने को लेकर आवेदन देने के दौरान प्रदेशाध्यक्ष विरेन्द्रसिंह सोलंकी, निजाम काजी, गिरजाशंकर दायम, प्रकाश धाकड़, रामगोपाल गेहलोत, दिनेश सैनी, इदरीश, मुकुंद सोलंकी, जीवन दायम, राजेश सालित्रा, शैलेश छाजेड़, राजेंद्र सिंह सोलंकी, जगदीश माली, पवन अखेडिया, भगवानदास बैरागी, दिनेश राठौर, प्रवीण जैन, निजाम काजी, कान्हा हाड़ा, इमरान मंसूरी, कपिल वास्तव, पंकज चारोडिया के साथ आसपास गांव से भी जमाकर्ता उपस्थित रहे।

इंदौर में सुगम यातायात के लिए विशेष प्रयास जारी

शहर में विभिन्न फ्लाईओवर, ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर के संबंध में चर्चा

सिटी चीफ । इंदौर में सुगम यातायात के लिए विशेष प्रयास जारी है। इसके तहत शहर में विभिन्न जगहों पर फ्लाईओवर, ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त कार्यों को गति देने के संबंध में चर्चा के लिए आज यहाँ कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.पी. अहिरवार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने विभिन्न फ्लाईओवर, ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर के संबंध में कराये गये फिजिबिलिटी सर्वे की उपयोगिता के संबंध में

चर्चा की। बताया गया कि उक्त कार्यों के संबंध में सभी पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों से व्यापक विचार विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा। बैठक में शहर में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों के संबंध में भी चर्चा की गई। संबंधित निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे की यातायात प्रभावित नहीं हो। वाहन चालकों को परेशानी नहीं हो। बारिश को देखते हुये जल निकासी के समुचित इंतजाम करें। गड्ढों का भी भराव करें।

महिलाओं एवं बच्चों के लिए क्रियान्वित योजनाएं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें

कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

सिटी चीफ । इंदौर । कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिये है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए क्रियान्वित योजनाएं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुँचे। बैठक में उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही एकीकृत बाल संरक्षण योजना एवं मिशन शक्ति के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बच्चों से संबंधित समस्त योजनाओं एवं संस्थाओं के कार्यों की पंजीकृत संख्या और उनको मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने इनके बेहतर संचालन के निर्देश दिये। वन स्टॉप सेंटर की गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने पंजीकरण और उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं में साप्ताहिक रूप से डॉक्टर का भ्रमण सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये। उन्होंने सभी संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्था को भी चाकचौबंद करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर पुलिस के आरक्षक और होमगार्ड भी तैनात किये जाये।

उन्होंने सीएसआर फंड से भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आँगनवाड़ी भवन सहित अन्य निर्माण कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करें। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर में आने वाली पीड़िताओं को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिये। उन्होंने बाल संरक्षण संस्थाओं में बच्चों के स्वास्थ्य, खान-पान, सुरक्षा आदि की बेहतर व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन, एडिशनल एसपी मती प्रियंका डुडवे, आईआईएम से कृष्णकांत, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया सहित सभी परियोजना अधिकारी सहित समस्त शासकीय /अशासकीय संस्थाओं के अधीक्षक एवं

जन-संवाद शिविर का लाभ जिन्हें मिला है वे अन्य लोगों को भी बतायें -मती यादव

वार्ड-34 के जयसिंहपुरा में जन-संवाद शिविर का आयोजन किया गया स्थानीय निवासियों ने विभिन्न समस्याएं विभागों के अधिकारियों के समक्ष रखी

सिटी चीफ । उज्जैन । शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मंशा के अनुसार राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदान करने तथा नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं से सम्बन्धित समस्याओं का वार्ड स्तर पर निराकरण करने के उद्देश्य से वार्ड-34 स्थित जयसिंहपुरा में जैन मन्दिर धर्मशाला में जन-संवाद शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति मती कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, स्थानीय पार्षद मती भारती विजय सिंह चौधरी एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। महापौर मुकेश टटवाल ने इस अवसर पर कहा कि नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर हो सके, इसके लिये जन-संवाद कार्यक्रम निरन्तर विभिन्न वार्डों में आयोजित किये जा रहे हैं। जन-संवाद शिविर में आमजन की ऐसी समस्याएं, जिनका त्वरित निराकरण किया जाना है तथा वे जिनमें शासन की प्रक्रिया के अन्तर्गत थोड़ा समय लगता है, उन सभी का निराकरण किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय जनता को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आमजन जन-संवाद शिविर में आयें और अपनी समस्याएं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को बतायें, उनका शीघ्र-अतिशीघ्र निराकरण किया जायेगा। सभापति मती कलावती यादव ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मंशा के अनुरूप जन-संवाद शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी जनता के बीच में उपस्थित होते हैं तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जन-संवाद शिविर के माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिला है, वे अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि अन्य लोग भी जन-संवाद शिविर के तहत लाभांवित हो सकें। जन-संवाद शिविर में

विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्याओं के आवेदन उन्हें दिये, जिनका शीघ्र-अतिशीघ्र निराकरण किये जाने का आश्वासन दिया गया। शिविर में स्थानीय निवासियों ने सभापति मती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और महापौर टटवाल के समक्ष भी अपनी कुछ समस्याएं रखी, जिनका शीघ्र-अतिशीघ्र निराकरण किये जाने का आश्वासन दिया गया।

फ्लोरीकल्चर मिशन के तहत चयनित किसानों को वितरित किए गए फूलों के पौधे

सिटी चीफ । ग्वालियर । नीम पर्वत का अवलोकन कर कलेक्टर ने पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के दिए निर्देश फ्लोरीकल्चर मिशन चरण-2 के तहत चयनित राज्यों के किसानों को मुफ्त में फूलों के पौधे वितरण करने एवं प्रशिक्षण देने के क्रम में शुक्रवार को ग्वालियर जिले के उदयपुरा गांव में सीएसआईआर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ की वैज्ञानिक टीम ने 50 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण एवं 5 लाख गेंदे के पौधो वितरित किए गए। इस मौके पर कलेक्टर मती रुचिका चौहान एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, सहायक संचालक उद्यानिकी एनपीएस बुन्देला एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित थे। कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत ने इस अवसर पर ग्राम पंचायत उदयपुर में स्थित नीम पर्वत का भी अवलोकन किया। उन्होंने नीम पर्वत पर निर्माणाधीन चिल्ड्रन पार्क

के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नीम पर्वत से लगे हुए तालाब पर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करने के साथ ही नीम पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर मती रुचिका चौहान ने कहा कि नीम पर्वत पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं को लाकर गतिविधियां बढ़ाई जाएं। इसके साथ ही नागरिकों को भी नीम पर्वत पर आयोजित गतिविधियों की जानकारी दी जाए, ताकि लोग परिवार सहित भी नीम पर्वत पहुँच सकें।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व तैयारी के संबंध में किया गया बैठक का आयोजन

सिटी चीफ । गुना । कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला अधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर डॉ. सिंह ने बताया कि विगत वर्ष की भांति दिनांक 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड पर किया जायेगा। कार्यक्रम स्थल लाल परेड ग्राउंड में प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व वर्ष की भांति सभी अधिकारी जिन्हें जो जिम्मेदारी दी गयी है उसका निर्वहन करें। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यालयों में प्रातः 8 बजे तक ध्वजारोहण का कार्य कर लिया जावे। ध्वजारोहण के दौरान ध्वज संहिता का पालन करते हुए किया जावे और झंडे का उपयोग सम्मानपूर्वक किया जावे। शिक्षण संस्थाओं में प्रभातफेरियों का आयोजन कर गरिमामयपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाये। जिले में मुख्य समारोह लाल परेड ग्राउंड में होगा, जिसमें मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। अंतिम रिर्हसल दिनांक 13 अगस्त 2024 को होगी। सभी अधिकारी दिनांक 12 अगस्त तक सभी मैदानी तैयारियां करना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में स्थित मुख्य सार्वजनिक भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व की इमारतों में दिनांक 14-15 अगस्त 2024 की रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था की जावे। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विधार्थी परेड में शामिल होंगे, इसे दृष्टिगत रखते हुए वाहनों पर्याप्त व्यवस्था आरटीओ के माध्यम से की जावे, साथ ही सांस्कृति कार्यक्रमों के लिए समिति द्वारा अच्छे कार्यक्रमों का चयन किया जावे, इसी प्रकार जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किये गये हैं, उनका परीक्षण कर पात्र लोगों की सूची भी तैयार कर 10 अगस्त 2024 तक भेज दी जावे। इसी प्रकार लोकतंत्र सेनानियों को कार्यक्रम स्थल पर लाने, ले जाने के लिए वाहन व्यवस्था एवं एक अधिकारी को लायजनिंग के लिये नियुक्त किया जावे।

संभागायुक्त वर्मा ने किया दो तहसील कार्यालयों का निरीक्षण

स्लीमनाबाद में ई- केवायसी और नक्शा तरमीम कार्य में वांछित प्रगति नहीं होने पर जताई नाराजगी

सिटी चीफ । कटनी । जिले में 31 अगस्त तक चलने वाले राजस्व महाअभियान 2.0 की प्रगति कार्य का जायजा लेनें कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा ने शुक्रवार को जिले के स्लीमनाबाद तहसील और कटनी के एस.डीएम कार्यालय व कटनी तहसील का औचक निरीक्षण किया।इस दौरान कलेक्टर दिलीप कुमार यादव एवं अपर कलेक्टर मती साधना परस्ते मौजूद रहे।

स्लीमनाबाद तहसील कार्यालय का निरीक्षण कमिश्नर वर्मा ने सर्वप्रथम स्लीमनाबाद तहसील का निरीक्षण किया और उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, नक्शा तरमीम, आदि कार्यो पर संतोष जताया। वहीं त्रुटि सुधार, अभिलेख दुरूस्तीकरण, ई- केवायसी और नक्शा तरमीम कार्य मे अपेक्षित प्रगति नही होने पर नाराजगी जाहिर

करते हुए आगामी 15 दिनों मे शत - प्रतिशत निराकरण कराने के निर्देश एस.डी.एम बहोरीबंद राकेश चौरसिया को दिए। **एस.डी.एम कार्यालय में समीक्षा** संभागायुक्त वर्मा ने कटनी एस.डी.एम कार्यालय में बैठकर तहसील और अनुविभाग मे राजस्व महाअभियान -2 के तहत राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व न्यायालयों मे प्रचलित अभिलेखों एवं प्रकरणों का निरीक्षण किया। वर्मा ने निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, ई- केवायसी, पीएम किसान सैचुरेशन, नक्शा तरमीम, आरसीएमएस न्यू डैश बोर्ड की प्रगति सहित राजस्व अभियान से जुड़े मामलों का गंभीरता से निराकरण सुनिश्चित हो। उन्होंने राजस्व अधिकारयों को नियमित रूप से राजस्व न्यायालयों में बैठने और लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिदायत दी की सभी प्रकरणों पर 31 अगस्त तक प्राथमिकता से निराकरण किया जाना सुनिश्चित हो । उन्होंने कटनी के राजस्व महाअभियान की प्रगति के प्रति संतोष जताया। इस दौरान एस.डी.एम प्रदीप कुमार मिश्रा सहित तहसीलदार बी.के.मिश्रा, नायब तहसीलदार अतुलेश सिंह, शिवभूषण सिंह और आकाशदीप नामदेव आदि अधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ पेश किया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नई दिल्ली। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने वायनाड भूस्खलन के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। बता दें कि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा किया था कि इस त्रासदी से पहले ही केरल सरकार को इसके बारे में सूचित किया गया था। लेकिन केरल सरकार ने इन सूचनाओं को नजरअंदाज किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 187 के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रश्न का प्रस्ताव पेश किया है। अपने शिकायत पत्र में जयराम रमेश ने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर कई दावे किए और बताया कि कैसे त्रासदी से काफी पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के बावजूद केरल सरकार की तरफ उनका उपयोग नहीं किया गया। इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्य-जांच की गई है। 2 अगस्त, 2024 को प्रकाशित एक ऐसी विस्तृत तथ्य-जांच संलग्न है।

अपने पत्र में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लिखा, यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठे साबित हुए हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य की तरफ से सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। इन परिस्थितियों में, हम प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

दिल्ली के शेल्टर होम में 20 दिन भीतर 13 बच्चों की मौत, जांच के आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के आशा किरण शेल्टर होम में 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत को लेकर फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली सरकार का आशा किरण शेल्टर होम है। जहां महज 20 दिन के भीतर ही 13 बच्चों की मौत हो गई है। इसको लेकर आतिशी ने कहा कि उनको मीडिया रिपोर्ट्स से जानकारी मिली है कि दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम में 13 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी मौत कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हैं। इस बात से यह पता चलता है कि बच्चों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पार रही हैं।इसके साथ ही आतिशी ने यही कहा कि ये खबर बहुत आश्चर्य करने वाला है। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन अगर ये घटना सच है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह एक गंभीर मुद्दा है। इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। जांच के लिए आतिशी ने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के 48 घंटे के भीतर ही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन

पीड़ित परिवार को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज

अयोध्या। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता समेत दो लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। पीड़िता और उसके परिजनों पर सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा था।सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। इस आरोप में सपा नेता व नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा व एक अन्य के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों पर रात 11:00 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार को सुलह करने की दी धमकी का आरोप लगा है।

गैंगरेप के आरोपी सपा नेताओं ने पीड़िता को धमकाया: बता दें कि पीड़िता जिला महिला अस्पताल में भर्ती है। आरोप है कि आरोपियों ने रात 11:00 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार को सुलह करने का दवाब बनाया और सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले थाना पूराकलंदर के भरतकुंड निवासी रामसेवकदास ने कोतवाली नगर में सपा नेता व नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

जानिए क्या है पूरा मामला: यह घटना अयोध्या के थाना क्षेत्र पूराकलंदर की है। यहाँ के चौकी क्षेत्र भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की बेकरी की दुकान है। जहां पर कुछ महिने पहले पीड़िता अपने मां के साथ मजदूरी कर वापस आ रही थी। रास्ते में मोईद की दुकान में कुछ समान लेने के लिए इसी दौरान दुकान में काम करने वाला राजू और उसके मालिक मोईद ने पीड़िता से बारी-बारी सामूहिक दुष्कर्म किया। इसी दौरान आरोपितों द्वारा रेप का वीडियो भी बना लिया गया। किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। बाद में इसी वीडियो से डरा-धमका कर पीड़िता से 2 महीने तक दोनों आरोपितों ने गैंगरेप किया। इस वजह से पीड़िता गर्भवती हो गई। लड़की के पेट में दर्द होने पर माँ को शक हुआ। जब यह बात लड़की की माँ को पता चली तो उसने पूरी वजह पूछी। पीड़िता ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। आखिरकार मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई।

आरोपियों को किया गिरफ्तार: इस मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता समेत दो लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या पुलिस ने 30 जुलाई को जिले के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा नगर में बेकरी संचालित करने वाले मोईद खान और उसके कर्मचारी राजू खान को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मोईद और राजू खान ने दो महीने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और इस कृत्य को रिकॉर्ड भी किया। यह घटना तब प्रकाश में आई जब हाल ही में मेडिकल जांच में पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला। यह दावा किया जाने के बाद कि मोईद खान सपा का सदस्य है, मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है।

पीड़िता के परिजनों से मिले योगी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के परिजनों से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की और आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का उनको भरोसा दिया। योगी ने कहा, ''दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाने के लिए कैप्टन शुभांशु शुक्ला का चुनाव

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने घोषणा की है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए आगामी भारत-अमेरिका मिशन पर उड़ान भरने के लिए चुना गया है। इसके साथ ही कैप्टन प्रशांत नायर को भी इस मिशन के लिए चुना गया है। वे बैकअप के तौर पर इस मिशन पर जाएंगे। इसरो ने कहा कि उसके मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने एक्सिओम-4 मिशन के लिए एक्सिओम स्पेस इंक, अमेरिका के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है। राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में दो गगनयात्रियों की सिफारिश की है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुख्य पायलट के रूप में चुना गया है, जबकि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप के रूप में चुना गया है। इसरो ने एक बयान में कहा कि असाइन्ड चालक दल के सदस्यों को बहुपक्षीय चालक दल संचालन पैनल (एमसीओपी) की ओर से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उड़ान भरने के लिए अंतिम रूप से मंजूरी दी जाएगी। अनुशंसित गगनयात्री अगस्त 2024 के पहले सप्ताह से मिशन के लिए अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। इसरो ने कहा कि अपने मिशन में गगनयात्री आईएसएस पर चयनित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रयोग करेंगे साथ ही अंतरिक्ष आउटरीच गतिविधियों में शामिल होंगे।

नीट यूजी पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ

नई दिल्ली। नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विस्तार से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि पेपर लीक का मामला सिस्टमैटिक फेलयर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है। नीट यूजी परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसके बाद 4 जून को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट सामने आने के बाद कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपने फैसले पर एनटीए की सभी खामियों पर बात की। हम छात्रों के हित में एनटीए की खामियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि नीट परीक्षा की सभी खामियां इसी साल दूर कर लेनी चाहिए ताकि दोबारा कभी ऐसी गड़बड़ी न हो।

बागपत में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जीजा-साले पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष में जीजा-साले की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी। यह वारदात बागपत के चांदीनगर इलाके के मंसूरपुर के जंगल में हुई। यहां पर गाजियाबाद के मुरादनगर के नवीपुर का कुलदीप अपने जीजा मंसूरपुर निवासी कवींद्र के पास गया था। रात में इनके पास ट्यूबवैल पर खैला गांव के कई युवक थे। वहां विवाद होने पर खैला के युवकों ने कुलदीप और कवींद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। कवींद्र को करीब 14 गोली लगी हैं और कुलदीप को 2-3 गोली लगी हैं। हत्या की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि आपसी संघर्ष में यह हत्याकांड हुआ है। मृतक का आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, दोनों हत्यारोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। हादसे के बाद गांव में तनाव का माहौल है।

कमला हैरिस होंगी डेमोक्रेटिक की तरफ से राष्ट्रपति पद की आधिकारिक उम्मीदवार

वाशिंगटन। अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को शुक्रवार को सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हैरिस पहली भारतीय-अफ्रीकी मूल की महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। पांच नवंबर को होने वाले आम चुनाव में हैरिस (59) का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगा। इस बीच, ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि उन्हें अपनी संभावित डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बहस में भाग लेना है या नहीं। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष जैमे हैरिसन ने देश भर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों की ऑनलाइन गिनती समाप्त होने के बाद कहा, ''मुझे यह पुष्टि करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि उपराष्ट्रपति हैरिस ने सभी सम्मेलन प्रतिनिधियों से बहुमत से अधिक वोट हासिल किए हैं और मतदान समाप्त होने के बाद वह डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधियों के बहुमत से उम्मीदवारी मिलने की घोषणा के बाद हैरिस ने कहा, ''मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने पर गौरवान्वित हूं। मैं अगले सप्ताह आधिकारिक रूप से नामांकन स्वीकार करूंगी। यह अभियान लोगों को देश प्रेम से प्रेरित होकर एकजुट होने और सर्वश्रेष्ठ के लिए लड़ने के बारे में है। हैरिस की मां भारतीय अमेरिकी थीं जबकि पिता अफ्रीकी मूल के जमैका निवासी थे। हैरिस पार्टी में अगले सप्ताह ऑनलाइन मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद आधिकारिक रूप से नामांकन स्वीकार करेंगी। वह 22 अगस्त को शिकागो में आयोजित डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार करेंगी। अगले कुछ दिनों में, वह उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी की घोषणा कर सकती हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा, ''ठीक है, मैं चाहता हूं। और हम अभी भी चुनावों में काफी आगे चल रहे हैं... वह (हैरिस) उनसे (जो बाइडन) बेहतर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः वह उनसे भी खराब होंगी। उन्होंने कहा, ''अगर मैं बहस नहीं करता, तो वे कहते, 'ओह ट्रंप बहस नहीं कर रहे हैं। यही बात वे अब भी कहेंगे। मेरा मतलब है कि अभी मैं कहता हूं, मुझे बहस क्यों करनी चाहिए? मैं चुनावों में आगे चल रहा हूं। और हर कोई उन्हें जानता है, हर कोई मुझे जानता है।

मध्य पूर्व में तनाव के बीच अमेरिका का सामने आया बड़ा फैसला

इजरायल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य ताकत की तैनात

नेशनल डेस्क। मध्य पूर्व में हाल ही में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने फैसला किया है कि वह क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाएगा। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और नौसेना के युद्धपोत तैनात करने की योजना बनाई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ईरान और उसके सहयोगी समूहों, जैसे कि हमास और हिजबुल्लाह, से संभावित खतरों का सामना करना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने घोषणा की है कि अमेरिका मध्य पूर्व और यूरोप में अतिरिक्त नौसेना क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजेगा, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, अमेरिका ने मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी भेजने का निर्णय लिया है। पेंटागन ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि इस सैन्य तैनाती का उद्देश्य अमेरिकी सेना की सुरक्षा को मजबूत करना, इजरायल की रक्षा में सहयोग बढ़ाना और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना है। पेंटागन ने पहले ही यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को क्षेत्र में तैनात किया था। अब, अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप% को तैनात करने का निर्णय लिया है, जो कि लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा। अमेरिका ने इससे पहले 13 अप्रैल को भी अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई थी, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के साथ इजरायल पर हमला किया था। उस समय, इजरायल ने अमेरिका और अन्य सहयोगियों की मदद से लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल के दौरान नए अमेरिकी रक्षात्मक सैन्य तैनाती पर चर्चा की। हाल ही में, ईरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की गई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और अयातुल्ला अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी। हमास का आरोप है कि इजरायल ने हानिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है, जबकि इजरायल ने इस आरोप को नकारा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने हमास नेता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर इजरायल पर हमला होता है, तो अमेरिका उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास हानिया की हत्या में इजरायल की भूमिका की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार, अमेरिका का सैन्य समर्थन और तैनाती मध्य पूर्व में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। यह कदम न केवल इजरायल की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि क्षेत्रीय तनाव को भी नियंत्रित करने में मदद करेगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569